

सृष्टि एग्रो



वर्ष: 02

अंक : 08

मुंबई: 16 मई से 31 मई 2014

मूल्य -2 रुपए

पृष्ठ : 12

महाराष्ट्र में बेमौसम ने बिगाड़ा हाल

पुणे। महाराष्ट्र में बिना मौसम की बरसात के चलते पांच लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद, सांगली और सोलापुर में बिजली गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि सोलापुर में ही बिजली के तार गिरने से दो लोग झुलस कर मारे गए।



और बिजली गुल होने से परेशानी भी हुई। प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर हुई बेमौसम बारिश ने पांच लोगों की जान ले ली है।

अचानक मौसम का मिजाज बदला और रिमझिम वर्षा ने शहर को तर-ब-तर कर दिया। अभी भी महाराष्ट्र के कई इलाके में रुक रुक कर बरसात हो रही है। बारिश के चलते प्रदेश के कई जगह पर बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की जानकारी मिली है।

पुणे, औरंगाबाद शहर सहित मराठवाड़ा के कई इलाकों में बुधवार को बेमौसम बारिश ने जन-जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। झुलसाती गर्मी के बीच बारिश ने लोगों को राहत तो दी, लेकिन उमस

दुनिया के प्रदूषित शहरों में विदर्भ के तीन शहर

चंद्रपुर। दुनिया के प्रदूषित शहरों में महाराष्ट्र के 12 शहरों के साथ विदर्भ के तीन शहर- नागपुर, अमरावती व चंद्रपुर भी शामिल हैं। इसके साथ ही चंद्रपुर देश के 124 शहरों में चौथा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। डब्ल्यूएचओ ने दुनिया के 91 देशों के 1600 शहरों में वातावरण व स्वास्थ्य पोषक वायु की उपलब्धता तथा अन्य मानकों पर सर्वेक्षण किया। इनमें से 500 शहर प्रदूषित व स्वास्थ्य की दृष्टि से घातक शहरों के रूप में चिन्हित किये गये हैं, जिसमें महाराष्ट्र के 12 शहरों के साथ विदर्भ के 3 शहर भी शामिल हैं। महाराष्ट्र के 12 प्रदूषित शहरों में मुंबई, नागपुर, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, चंद्रपुर, कोल्हापुर, नाशिक, सांगली, सोलापुर, ठाणे व नवी मुंबई शामिल हैं। ब्यूएचओ के सहायक महानिदेशक डॉ. फ्लाविया बुस्ट्रो ने कहा कि इन शहरों में खुली हवा में सांस लेना मुश्किल है। लोगों को अच्छी व स्वच्छ वायु देने में वे विफल साबित हो रहे हैं। इसके परिणाम बच्चों तथा बुजुर्गों को भुगतने पड़ेंगे।

सभी फसलों की उत्तम एवं भरपूर पैदावार के लिये



हिन्दकेम के उत्कृष्ट उत्पाद



मैगनेट

सरदार-जी

अमृत गोल्ड



Hindchem Corporation

307, Linkway Estate, Above Greens Restaurant,
New Link Road, Malad (W), Mumbai-400064
Tel : 91-22-66998360 / 66998361 • Fax : 91-22-66450908
Email : admin@hindchem.com
Website : www.hindchem.com

विदर्भ में नहीं होगी पानी की किल्लत

नागपुर। गर्मी के मौसम में जलस्तर नीचे जाने से लोगों पानी के लिए काफी जद्दोजहद करनी होती है। पर इस मामले में विदर्भ के संबंध में कुछ राहत का अनुमान है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले विदर्भ में स्थिति काफी कुछ ठीक है। दरअसल सूबे के प्रमुख जलाशयों में इस बार जलस्तर उतना कम नहीं हुआ है, जितना की गत वर्ष इसी दौरान देखने को मिला था। अधिकारियों की मानें तो इस बार जलाशयों में पानी पर्याप्त मात्रा में होने से कम से कम पीने के पानी की आपूर्ति तो अगले दो माह तक पर्याप्त मात्रा में हो



ही सकती है। अधिकारियों के मुताबिक नागपुर व अमरावती संभागों में स्थिति और भी अच्छी दिखाई दे रही है। अधिकारियों के मुताबिक यदि इस माह के अंत में पारा और ऊपर जाता है, तो वाष्पिकरण के कारण पानी का स्तर प्रति

सप्ताह एक से दो फीसदी की दर से कम हो सकता है। इस बीच सुखद बात यह भी है कि पिछले चार-पांच दिनों से गत वर्ष इसी समय की तुलना में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है।

नागपुर संभाग : 16 प्रमुख जलाशयों में जलस्तर कुल क्षमता का 53 फीसदी है।

अमरावती संभाग : यहां के प्रमुख बांधों में जलस्तर कुल क्षमता का 46 फीसदी है।

उक्त दोनों ही संभागों में जलस्तर पिछले वर्ष के मुकाबले क्रमशः 35 और 29 फीसदी अधिक है।

17 मई तक हो सकती है मानसून की दस्तक

पुणे। अरब सागर और हिंद महासागर में साउथ वेस्ट मानसून सक्रिय हुआ है। इससे देश में मानसून के आगमन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले तीन दिनों यानि 17 मई तक मानसून दक्षिण अंडमान और बंगाल के समुद्रीय तट पर पहुंचेगा। अगर मौसम का मिजाज ऐसा ही रहा तो मानसून देश में सही समय पर पहुंच सकता है। हर साल मानसून 20 मई तक अंडमान और बंगाल की खाडियों में पहुंचता है, लेकिन इस साल मानसून के दो तीन दिन पहले पहुंचने के आसार हैं।

फिर से कृषि आमदनी बीमा योजना होगी आरंभ : राजनाथ सिंह

मुंबई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने लातूर निलंगा इलाके में चुनावी रैली में किसानों को बताया। अगर यह पार्टी केंद्र में सत्ता पर आती है तो वे किसानों को लागत का 50 प्रतिशत मुनाफा सुनिश्चित कराएंगे। राजनाथ सिंह जब कृषि मंत्री थे, तब उन्होंने कृषि आमदनी बीमा योजना शुरू की थी। इस योजना से यह अंदाज लगाया जाता था कि इस बार

फसल से कितनी आमदनी हो सकती है। अगर किसी कारणवश फसल बर्बाद हो

जाती हो तो बीमा कंपनी पहले से तय न्यूनतम कीमत किसान को अदा करेगी। उस वक्त यह योजना प्रयोग के तौर पर 30 जिलों में लागू की गई थी। राजनाथ सिंह ने

बताया की इस बार बीजेपी अगर सत्ता पर आती है, तो यह योजना नए रूप में लागू कि जाएगी।





संपादकीय

कुचक्र से जूझते जन आंदोलन

देश के कई हिस्सों में जल, जंगल और जमीन के अधिग्रहण के विरोध में आंदोलनकारी सक्रिय हैं। लेकिन सत्ता में बैठे लोग उन आवाजों की निरंतर अनसुनी कर रहे हैं। ऐसे में करोड़ों लोगों के विस्थापित और बेरोजगार होने का खतरा बढ़ गया है। पूरी दुनिया में जमीन और पानी को लेकर संघर्ष जारी है। एक तरफ बड़े-बड़े उद्योगपति-पूंजीपति हैं जो सारे साधनों-संसाधनों पर कुंडली मार कर बैठ जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ छोटे किसान, भूमिहीन और वंचित समाज के लोग हैं, जो चाहते हैं कि भूमि पर उनको भी थोड़ा अधिकार मिले। जिससे वे देश, परिवार और समाज के लिए अन्न पैदा कर सकें। विडंबना है कि देश के प्राकृतिक संसाधनों को लूटने वाले लोग एकजुट हैं और सत्ता में बैठे लोगों से उनकी गलबहियां हैं।

ऐसे में वंचित वर्ग के लोगों को सरकार से अब कोई उम्मीद नहीं रह गई है। उनके सामने अब अपने हक के लिए आंदोलन के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। आजादी के बाद पिछले छह दशकों में देश के गरीब किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और घुमंतू जनजाति के लोगों के सामने रोजी-रोटी की समस्या विकराल हो गई है। अब वे अपने वजूद बचाने के लिए आंदोलन पर उतर आए हैं। मीडिया और राजनीतिक दलों की निष्ठा भी अब गरीबों और वंचितों के हक को दिलाने में नहीं रह गई है।

देश के विभिन्न राज्यों में चल रहे जन आंदोलन के मर्म को खंगालें तो महात्मा गांधी के पौत्र और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे गोपालकृष्ण गांधी की यह बात सही लगती है कि देश में बड़ी कंपनियां समांतर सरकार की तरह काम कर रही हैं और चुनी हुई सरकार तमाशबीन बन कर रह गई है। सरकारों ने वंचितों के हक में कोई कारगर कानून तो बनाया नहीं पर कंपनियों के लिए गरीबी के हक में बने कानूनों को ही बदल दिया है।

जमीन का मामला राजनीतिक पार्टियों के घोषणापत्रों से अब गायब हो गया है और सरकारों ने भूमि कानूनों को भी बड़ी कंपनियों के हक में बदल दिया है। आज भारत सहित पूरी दुनिया में बनाए गए विकास के नए मॉडल टूटते जा रहे हैं। इसके साथ ही भूमंडलीकरण के साथ आए आक्रामक विकास की अवधारणा ने राज्यों को शक्तिशाली और जनता को निहत्था और निरुपाय कर दिया है।

आज देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां गरीबों और वंचितों का आंदोलन नहीं चल रहा हो। केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नगालैंड और मेघालय जैसे राज्यों में सरकारों की जनविरोधी नीतियों और वनाधिकार कानूनों के लागू न होने पर जहां आदिवासी फिर से ठगे महसूस कर रहे हैं, वहीं बढ़ती भूमिहीनता और आवासहीनता के कारण लोग अपनी जड़ों से उखड़ रहे हैं और पलायन करने को मजबूर हैं। इन सभी राज्यों में राजनीतिक पार्टियों की ओर से बेहतर सरकार देने के बड़-चढ़ कर दावे किए जाते हैं पर हकीकत कोसों दूर है।

परियोजनाओं में अपनी भूमि गवां चुके किसान गुस्से में हैं। हमे उनके गुस्से के कारणों को जल्द समझना होगा और निदान करना होगा।

सुरेश शर्मा
(प्रधान संपादक)



डॉ. अशोक कुमार शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि प्रसार सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर, राजस्थान

हमारी प्राकृतिक सम्पदा में मिट्टी का महत्व सबसे अधिक है और शायद हम मिट्टी के स्वास्थ्य की कद्र नहीं कर मिट्टी की ही सबसे ज्यादा मिट्टी कर रहे हैं। उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत बनने में तीन हजार साल से लेकर 12 हजार साल तक लग जाते हैं और मिट्टी खराब हो जाती है तो उसे सुधारने में अत्यधिक जोर आता है। विकासशील देशों में मिट्टी की बर्बादी पर विश्व खाद्य संगठन ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि अगर इसी तरह से मिट्टी की बर्बादी होती रही तो विकासशील देशों की उत्पादन क्षमता में 20 प्रतिशत तक कमी आ सकती है। अतः खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से हमें भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना है।

मिट्टी के हालात नाजुक

प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन की अश्वत्थामा में गठित टास्क फोर्स की रिपोर्ट के अनुसार उर्वरा शक्ति की दृष्टि से 75: भूमि का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। मिट्टी में आर्गेनिक कार्बन की 82: की

कमी होकर आर्गेनिक कार्बन की मात्रा न्यून श्रेणी (0.5 प्रतिशत) में है। आर्गेनिक मात्रा की कमी के कारण भूमि में नत्रजन की मात्रा में 90 प्रतिशत तक की कमी आ गई है जिसकी पूर्ति के लिए रासायनिक खाद यूरिया का अंधाधुंध उपयोग करने एवं फसलों की सघनता बढ़ने के कारण मौलिक उर्वरा शक्ति घटने के साथ ही भूमि की भौतिक संरचना भी बिगड़ रही है। इससे जमीन कठोर और क्षारीय बन रही है। फास्फोरस की भी 64: तक कमी हो गई है। राइजोबियम, एजेटोबेक्टर, ट्राइकोडर्मा जैसे मित्र जीवाणुओं की संख्या घट रही है जो भविष्य में अत्यन्त नुकसानदेह है। भूमि में गिरावट आदि का प्रमुख कारण पोशक तत्वों के अलावा भूमि में गौण व सूक्ष्म तत्वों की कमी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जैसे गंधक, जस्ता, लोहा, तांबा, मैंगनीज आदि।

कैसे सुधारें मृदा स्वास्थ्य

भूमि की उर्वरा शक्ति मुख्यतः भूमि की ऊपरी परत से लेकर भूमि की 6-7 सेंटीमीटर (दोई-तीन इंच) नीचे तक ही पाई जाती है। इसके नीचे की मिट्टी पानी को धारित करती है। किसान जुताई इसी ऊपरी उपजाऊ परत को ढीला करने के लिए करते हैं। यदि मिट्टी की इस ऊपरी परत के बचाव के लिए किसान खेत के चारों ओर मेड़ नहीं बनाए तो वर्षा पानी से ये जुती हुई मिट्टी बह सकती है तथा इस प्रकार यह जरूरी है कि टिकाऊ एवं सतत उत्पादन के लिए भूमि के कटाव व क्षरण को रोका जाए। इस प्रकार भू संरक्षण एवं पानी संरक्षण दोनों आवश्यक हैं। अन्य उपायों में भूमि में मित्र जीवाणुओं की वृद्धि करना, उचित नमी बनाए रखना, मिश्रित फसलें बोना, हरी खाद गोबर की खाद, कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट, खाद देना, संरक्षण हेतु पलवार बिछाना, जिप्सम, सार्वजनिक एवं निजी भूमियों में जल ग्रहण प्रवृत्ति बढ़ाना, चैकडेम बनाना आदि महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार अवषेशों को खेत में जलाने की बजाय उसे भूमि में मिला देना अच्छा रहता है। वर्षा ऋतु में उपलब्ध घासफूस (खरपतवार) से कम्पोस्ट खाद बनाकर खेतों में डालना चाहिए। इस प्रकार एकीकृत उपायों को अपनाकर भूमि की उपजाऊ शक्ति को मजबूत करना चाहिए।

भूमि सुधार के कुछ महत्वपूर्ण उपाय

मिट्टी परीक्षण क्यों एवं कैसे- अगर कोई व्यक्ति अपने आप को बीमार महसूस करता है तो बीमारी का कारण क्या है तथा उसकी सही दवा क्या हो इसे जानने के लिए उसे डाक्टर के पास जाना पड़ता है। डाक्टर बुखार नापने के लिए थर्मामीटर से ताप नापकर पता लगाता है कि बुखार मामूली है या ज्यादा। इसी प्रकार खून जाँच कर खून की कमी का पता लगाता है। मलेरिया के लिए भी रक्त जाँच की जाती है। बीमार आदमी बोलकर कुछ पीड़ा के लक्षण तो बता सकता है लेकिन खेत की मिट्टी अपने बारे में बोलकर नहीं कह सकती कि उसमें कितने पोशक तत्वों की कितनी मात्रा मौजूद है एवं कितनी किस फसल के लिए और चाहिए। इस प्रकार किसी भी फसल के पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए कई पोशक तत्वों की आवश्यकता होती है जिनके अभाव में पौधे अपना जीवन चक्र सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं कर पाते। प्रायः पोशक तत्वों की कमी भूमि में धीरे-धीरे पनपती है और पौधों पर जब पोशक तत्वों की कमी के चिन्ह प्रकट होने लगते हैं तब तक काफी देर हो चुकी होती है और फसल की पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है।

अतः खेत की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का सही आंकलन करवाना आवश्यक है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि निरन्तर अच्छी पैदावार पाने के लिए खेत में कौन-कौन सी खाद व उर्वरक कितनी मात्रा में डालें। ऐसा मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही संभव है। बिना मिट्टी जाँच कराए उर्वरक डालेंगे तो क्या नुकसान होंगे

-जरूरत से कम उर्वरक डालने से पैदावार कम।

-जरूरत से ज्यादा उर्वरक डालने से धन की हानि एवं फसल को नुकसान

-मिट्टी खराब होना।

-नत्रजन, फास्फोरस, पोटाश का वास्तविक अनुपात 3: 2: 1 है जो यह प्रदर्शित करता है कि पोटाश की तुलना में नत्रजन व फास्फोरस का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। इससे भूमि में पोशक तत्व होते हुए भी पौधों को नहीं मिलते हैं। इसलिए मिट्टी की जाँच करवाकर ही उर्वरकों का प्रयोग करें।

मिट्टी परीक्षण के उद्देश्य

-मिट्टी की उर्वरा शक्ति की जाँच करके एवं किस्म विशेष के लिये पोशक तत्वों की संतुलित मात्रा की सिफारिश करना।

-मिट्टी में लवणता, क्षारीयता तथा अम्लीयता की पहचान एवं जाँच के आधार पर भूमि सुधारकों की मात्रा एवं प्रकार की सिफारिश करना।

-मिट्टी के भौतिक एवं रासायनिक गुणों की जाँच कर गुणों के अनुसार उपयुक्त फसलों व फसल किस्मों की सिफारिश करना।

-फलों के बाग लगाने के लिये भूमि की उपयुक्तता का पता लगाना।

मिट्टी का नमूना लेने एवं परीक्षण के चरण

-मिट्टी के नमूनों को एकत्र करना।

-नमूनों को तैयार करना।

-मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में मिट्टी परीक्षण करना।

-मिट्टी परीक्षण के नतीजों के आधार पर उर्वरक संस्तुति करना।

सामान जो चाहिए नमूना लेने के लिए

मिट्टी का नमूना लेने लिए खुरपी, फावड़ा, बाल्टी, ट्रे या प्लास्टिक का टब, कपड़े एवं प्लास्टिक की थैली,

पेन, धागा, नमूना पत्रक इत्यादि की आवश्यकता होती है जो किसी भी किसान के पास उपलब्ध होता है। नमूना लेने के लिए सभी सामान साफ होने चाहिये, जिससे मिट्टी दूषित न हो।

फसल उत्पादन के लिए नमूना लेने का सही तरीका

-नमूना ऐसी जगह से लिया जाये कि उन मिट्टियों का वास्तविक प्रतिनिधित्व कर सके। खेत को उसकी स्थिति (समतल, ऊँची, नीची, ढलान) एवं मिट्टी की किस्म के अनुसार बांट लेते हैं।

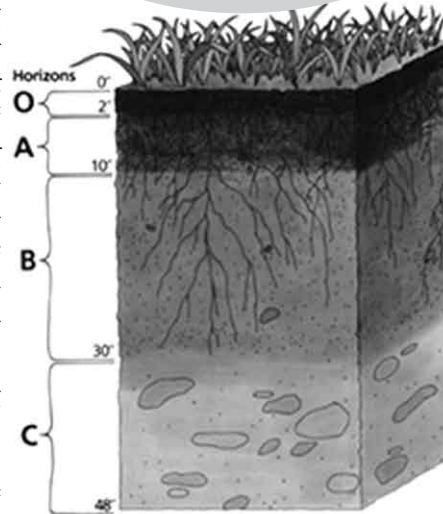
-नमूना लेने के लिए लगभग एक हैक्टर क्षेत्र से 15-20 स्थानों का चयन करते हैं।

-नमूना लेने वाले स्थान से घास-फूस इत्यादि साफ कर लेते हैं। खुरपी या फावड़े की सहायता से लगभग 15 से.मी. गहरा अंग्रेजी के आकार का गड्ढा खोदकर किसी भी तरफ से पूरी गहराई तक की मिट्टी की एक समान परत काटकर किसी साफ बाल्टी में एकत्र कर लेते हैं।

-एकत्रित नमूनों को आपस में अच्छी प्रकार से मिला लें एवं छाया में सुखायें। सुखाने के बाद नमूनों के ढेलों को फोड़कर बारीक बनाकर खरपतवार, पौधों की जड़ें, कंकड़, पत्थर आदि को निकालकर फेंक दें। मिलाई हुई मिट्टी को चार भागों में बाँटकर आमने-सामने की दो भागों की मिट्टी को रखकर बाकी फेंक दें। रखे हुए दो भागों की मिट्टी को अच्छी तरह मिला लें और पूर्ववत फेला कर चार बराबर भागों में बाँट लें। पहले की तरह दो भाग की मिट्टी रख कर दो भाग फेंक दें। यह क्रिया तब तक जारी रखें जब तक मिट्टी का कुल नमूना लगभग 500 ग्राम न रह जाए। वास्तव में इस तरह इकट्ठा किया गया मिट्टी का नमूना ही प्रतिनिधि नमूना कहलाता है।

-आधा किलो मिट्टी को किसी साफ पॉलिथीन या कपड़े की थैली में भरकर उसमें पहचान के लिए सूचना पत्रक को अन्दर डालकर प्रयोगशाला में भेज दे। सूचना पत्रक में किसान का नाम एवं पूरा पता, खेत की पहचान, नमूना लेने की तिथि, जमीन का ढलान, सिंचाई का शेष पृष्ठ - 8 पर

मिट्टी का सुधार- अच्छी फसल का आधार



सृष्टि एगो

सत्यापित शीर्षक क्रमांक : RAJHIN16932/20/1/2014-TC

वर्ष: 01

अंक : 05

जयपुर : 16 मई से 31 मई 2014

मूल्य -2 रुपए

पृष्ठ : 12

कालीसिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट आरंभ

जयपुर। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के झालावाड स्थित कालीसिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट की 600 मेगावाट क्षमता वाली पहली इकाई ने व्यावसायिक विद्युत उत्पादन आरम्भ कर दिया है। इस इकाई से राज्य ग्रिड को औसतन 1३० लाख यूनिट अतिरिक्त बिजली प्रतिदिन मिलेगी। कालीसिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट की 600 मेगावाट की इस नवनिर्मित पहली इकाई को विभिन्न परीक्षणों के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा था। लगातार 72 घंटे पूर्ण क्षमता पर संचालन के फलस्वरूप अब इस इकाई को व्यावसायिक उत्पादन उपयुक्त माना गया है इस परियोजना के अन्तर्गत 600 मेगावाट क्षमता की द्वितीय इकाई भी निर्माणाधीन है, जिसका निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है।

प्रभुलाल सैनी ने बादल से भेंट की

जयपुर। पंजाब प्रभुलाल सैनी रामबाग पैलेस बादल ने जैतून और श्री बादल जा रहे पंजाब के पिंड खजूर इच्छा जाहिर और डेयरी प्रयासों को



के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से कृषि मंत्री ने जयपुर में शिष्टाचार भेंट की। श्री सैनी ने होटल में श्री बादल से मुलाकात की।

कृषि मंत्री से राजस्थान में की जा रही पिंड खजूर की खेती पर चर्चा की। ने राज्य में इनकी खेती के लिए किए प्रयासों की भी प्रशंसा की।

मुख्यमंत्री ने राज्य में जैतून और के कृषि फार्मों के अवलोकन की भी की। श्री बादल ने राज्य में पशुपालन के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए जा रहे भी सराहा।

बादल ने कृषि मंत्री को राजस्थान में गो पालन विभाग गठित किए जाने पर बधाई दी। मुलाकात करीब एक घंटे चली। उल्लेखनीय है कि बादल निजी यात्रा पर जयपुर आए थे।

खेती व कृषि संबंधी कार्यों को नरेगा से जोड़ा जाएगा-कृषि मंत्री

जयपुर। कृषि, पशुपालन, मत्स्य, डेयरी एवं कृषि विपणन मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुधरा राजे की पहल पर राज्य में पहली बार खेती व कृषि संबंधी कार्यों को नरेगा से जोड़ने का फैसला किया है, जो काश्तकारों के लिए वरदान साबित होगा। उन्होंने काश्तकारों से आह्वान किया है कि वे आधुनिक युग के अनुसार खेती की नवीनतम तकनीक को अपनाएं और फसल उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हुए आत्म निर्भर बनें।

सैनी बांसवाड़ा जिले की घाटोल तहसील के पड़ोली गोर्धन ग्राम में कृषि विभाग की ओर से आयोजित संभाग स्तरीय एक दिवसीय संकर मक्का बीज उत्पादन प्रेरणा मेले में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वसुधरा राजे ने राज्य में खेती व कृषि सम्बन्धी कार्यों को नरेगा से जोड़ने का ऐतिहासिक फैसला किया है, जिससे काश्तकारों को खेती के कार्य में नई दिशा तो मिलेगी वहीं, नरेगा के माध्यम से संचालित कार्यों में खेती कार्यों को जोड़ने से काश्तकारों को लाभ भी मिलेगा।

कृषि मंत्री सैनी ने कहा कि राज्य खाद्यान्न व दलहन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने सरसों का उदाहरण देते हुए कहा कि देश में उत्पादित होने वाली कुल सरसों का अकेले राजस्थान में 42 प्रतिशत उत्पादन हो रहा है। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों से कहा कि वे अन्न में प्रोटीन, पौष्टिकता और गुणवत्ता बढ़ाने के क्षेत्र में भी विशेष अनुसंधान करें। उन्होंने कहा कि सरकार काश्तकारों की मदद के लिए पूरी तरह संकल्पित है और खेती में नवीनतम नवाचारों के साथ काश्तकारों को प्रमाणित खाद-बीजों के माध्यम से उनकी फसल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने काश्तकारों से कहा कि वे इस मेले के माध्यम से दी गई खेती की नवीनतम तकनीक को अमल में लाएं।

राज्य बनेगा जैतून स्टेट



मिलेगी। उन्होंने कहा कि जैतून की खेती से राज्य जैतून (ऑलीव) तेल स्टेट बनेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान मसालों के उत्पादन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है।

वागड़ में अन्तरराष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक मक्का पर करेंगे अनुसंधान

कृषि मंत्री सैनी ने कहा कि वागड़ की आबोहवा एवं भूमि की उर्वरकता मक्का फसल के लिए उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि



कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किए गए बेहतर बीज का अनुसंधान किए जाने की वजह से ही यहां पर मक्का की उत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तरी हुई है। उन्होंने कहा

कि कहा कि अन्तरराष्ट्रीय स्तर के कृषि वैज्ञानिक वागड़ में मक्का के अनुसंधान के लिए आगे आएं और इसके बारे में अनुसंधान करेंगे। उन्होंने कहा कि वागड़ क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का फसल उत्पादन को देखते हुए सरकार भी कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से खेती में नवीनतम तकनीक को काश्तकारों तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है।

वागड़ की भौगोलिक स्थितियों के आधार पर बनेगी विशेष कार्ययोजना

कृषि मंत्री सैनी ने कहा कि सरकार वागड़ क्षेत्र के दोनों जिलों की भौगोलिक स्थितियों के आधार पर विशेष कार्ययोजना तैयार करेगी ताकि यहां के काश्तकारों को लाभ मिल सके। समारोह की अध्यक्षता करते हुए घाटोल विधायक नवीनतलाल निनामा ने कहा कि सरकार काश्तकारों के उत्थान के लिए नवीनतम तकनीक का प्रदर्शन काश्तकारों के खेतों में उन्हें अधिक फसल उत्पादन के लिए प्रमाणित बीजों के माध्यम से उन्हें प्रेरित करें ताकि यहां के काश्तकार भी अपनी खरीफ फसल उत्पादन क्षमता में वृद्धि कर सकें। उन्होंने कृषि मंत्री से किसानों के लिए मांग के अनुरूप खाद-बीज समय पर मुहैया करवाने की मांग की ताकि काश्तकार समय पर खरीफ फसलों की बुवाई कर सकें।

प्रदर्शनी भी बनी आकर्षण केन्द्र

राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था द्वारा आयोजित बीज उत्पादन प्रेरणा मेले में कृषि विभाग की ओर से काश्तकारों को नवीनतम खेती तकनीक अपनाने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से लगाई गई प्रदर्शनी भी आकर्षण का केन्द्र रही। बड़ी संख्या में उपस्थित काश्तकारों ने संकर मक्का बीज उत्पादन के उपयोग के माध्यम से मक्का के फसल की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के बारे में दिखाई गई जानकारी को देखा। इस अवसर पर काश्तकारों को संकर मक्का बीज उत्पादन सहित अन्य प्रमाणित बीजों के उपयोग के बारे में पेम्पलेटों का भी वितरण किया गया।

इस मौके पर भारत सरकार के कृषि आयुक्त जी.एस.संधु, सीमीर समस्तीपुर (बिहार) के वैज्ञानिक डॉ. राजकुमार, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के निदेशक पी.एल.मालीवाल, कृषि अनुसंधान केन्द्र, बोरवट के संभागीय निदेशक डॉ. जी.एस.आमेटा, राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था, जयपुर के निदेशक मधुसूदन शर्मा सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थिति थे।

कृषि अधिकारी सजग होकर कार्य करें -अतिरिक्त मुख्य सचिव

जयपुर। कृषि एवं पशुपालन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अशोक सम्पतराम ने कहा है कि कृषि अधिकारी सजग होकर कार्य करें, ताकि किसानों को सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं का सही समय पर अधिक फायदा मिल सके।

सम्पतराम यहां पंत कृषि भवन में आयोजित कृषि विभाग के अधिकारियों की राज्य स्तरीय खरीफ अभियान कार्यशाला में बोल रहे थे। श्री सम्पतराम ने खेततलाई (फार्मपौंड) की उपयोगिता को रेखांकित करते हुए कहा कि विभागीय अधिकारी किसानों का चयन शीघ्र कर लें, ताकि उन्हें सही समय पर इस योजना का लाभ मिल सके। कार्यशाला में किसानों को मिलने वाली अनुदान राशि के बारे में सम्पतराम ने कहा कि किसानों को मिलने वाली अनुदान राशि में किसी प्रकार की देरी बर्दास्त नहीं की जाएगी। श्री सम्पतराम ने कहा कि सरकार कृषि के विकास के लिए खूब पैसा खर्च कर

रही है इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि उस पैसे का सही उपयोग हो।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कृषि अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे क्षेत्र में जाकर किसानों की असल समस्याओं से रूबरू हों, ताकि उनका सही समय पर समाधान हो सके। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सुगम पोर्टल के जरिए किसानों से प्राप्त समस्याओं का निपटारा तत्काल सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों की निरन्तर समीक्षा करने की बात भी कही।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे किसानों को दलहनी व तिलहनी फसलों में डीएपी की तुलना में सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करें। उल्लेखनीय है कि सिंगल सुपर फास्फेट राजस्थान में बहुतायत में पाया जाता है और यह डीएपी की तुलना में किफायती भी है।



संपादकीय

पर्यावरण...खतरे की चेतावनी

आज हमारे सामने विकास बनाम पर्यावरण का मुद्दा है और दोनों में से किसी को भी त्यागना संभव नहीं इसलिए समन्वित दृष्टिकोण के साथ वैश्विक हितों को साझा किया जाना चाहिए। यह ठीक है कि विकासशील देश चाहते थे कि उनको वह पूंजी और तकनीकी मिले ताकि वे पर्यावरण बचाने के साथ साथ अपने विकास को भी बनाए रख सकें। क्योंकि पर्यावरण की चिंताओं के बीच भी वे विकास को पर्यावरण के आगे कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं थे और न होंगे। हालांकि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की अंतर-सरकारी समिति ने भारी-भरकम रिपोर्ट जारी करते हुए यह आगाह किया है कि अगर दुनिया के देश गर्म होने वाली गैसों के प्रदूषण में कमी नहीं लाते तो ग्लोबल वार्मिंग से होने वाला नुकसान बेकाबू हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग से सिर्फ ग्लेशियर ही नहीं पिघल रहे, बल्कि इससे लोगों की खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और रहन-सहन भी प्रभावित होने लगा है।

कुछ देश और कुछ संगठन तब तक ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक दुनिया के धनी देश प्रयास न करें। भारत जैसे विकासशील देशों को आधारभूत ढांचा सुधारने, खाद्य सुरक्षा मजबूत करने, आपदा प्रबंधन तंत्र सुधारने, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और ताप वृद्धि के कारकों पर नियंत्रण की जरूरत है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में करीब 12 लाख हेक्टेयर में हुए ओला बारिश से गेहूं, कपास, ज्वार, प्याज जैसी फसल खराब हो गई थी। यह अनियमित वर्षा के कारण माना जा रहा है, जोकि ग्लोबल वार्मिंग का असर है। मौसम में अप्रत्याशित बदलाव से उपजी आपदाएं हमें ग्लोबल वार्मिंग के खतरे बताती रही हैं। दुनिया के संपन्न देश इसे अनदेखा करते रहे हैं। गरीब देशों की अपनी मजबूरियां हैं।

किसानों और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों जैसे घर से बाहर काम करने वाले वर्ग को नए संभावित खतरों के प्रति आगाह किया गया है। मनुष्य को बाढ़ और अत्यधिक गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया की आबादी बढ़कर सात अरब के आसपास हो गई है। ग्लोबल तापमान में वृद्धि का सिलसिला जारी है। आबादी बढ़ने से प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ा है और प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र सीमित होने के कारण भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। इसके बावजूद हमने अंधाधुंध विकास की जगह वैकल्पिक समाधान को नहीं अपनाया है। टिकाऊ विकास की चुनौती आज भी हमारे सामने बनी हुई है। बीते दो दशक में यह स्पष्ट हुआ है कि नवउदारवादी और निजीकरण नीति ने हमारे सामने बहुत-सी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। भूख, खाद्य असुरक्षा और गरीबी ने न केवल गरीब देशों पर असर डाला है। बल्कि पूर्व के धनी देशों को भी परेशानी में डाल दिया है। हमारे जलवायु ईंधन और जैव-विविधता से जुड़े संकटों ने भी आर्थिक विकास पर असर दिखाया है।

सचमुच आज हमारे सामने विकास बनाम पर्यावरण का मुद्दा है और दोनों में से किसी को भी त्यागना संभव नहीं इसलिए समन्वित दृष्टिकोण के साथ वैश्विक हितों को साझा किया जाना चाहिए। यह ठीक है कि विकासशील देश चाहते थे कि उनको वह पूंजी और तकनीकी मिले ताकि वे पर्यावरण बचाने के साथ साथ अपने विकास को भी बनाए रख सकें। क्योंकि पर्यावरण की चिंताओं के बीच भी वे विकास को पर्यावरण के आगे कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं थे और न होंगे। हालांकि यह कहते हुए भी विकासशील देश यह चाहते थे पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने में वे पूरी तरह से दुनिया के साथ हैं और ये कभी नहीं चाहेंगे कि धरती पर प्रदूषण का खतरा बढ़े।

लेकिन विकसित देश अपने लाभ और विकास के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहते हैं। जाहिर है कि विकसित देश पर्यावरण को हानि पहुंचाने में सबसे अधिक भूमिका निभा रहे हैं और सीमित प्राकृतिक संसाधनों का उन्होंने ही जमकर शोषण किया है, इन स्थितियों में विकासशील देशों से पर्यावरण के प्रति अधिक पहल करने की उम्मीद करना तर्कसंगत नहीं माना जा सकता है।

दरअसरल ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा मुद्दा है जो पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है और इसे बिना आपसी सहमति और ईमानदार प्रयास के हल नहीं किया जा सकता है। आवश्यकता है मिल कर प्रयास करने की।

सुरेश शर्मा
(प्रधान संपादक)

रबी फसलों की कटाई के उपरांत ही जब खेत में कुछ नमी हो तब ही खेतों की गहरी जुताई आसानी से की जा सकती है। ज्यादातर क्षेत्रों में अप्रैल के द्वितीय सप्ताह तक सभी खेत खाली हो जाते हैं और किसान के पास खेतों की गहरी जुताई करने का पर्याप्त वक्त होता है। अतः मई व जून के महिनों में तापमान लगभग 40-50 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इतने अधिक तापमान पर खेतों में फसलों को हानि पहुंचाने वाले रोगाणु, कीटों के अण्डे, कीटों की शंखी अवस्था खेत जुतने से ऊपर

सतर पर आजाते हैं और सूर्य की तपन से नष्ट हो जाते हैं। यही अनावश्यक अवशेष एवं खरपतवार की जड़ों के साथ होता है। खरपतवार की जड़ें व बीज गहरी जुताई करने से ऊपरी सतह पर आ जाते हैं और अधिक तापमान के प्रभाव से सूख कर नष्ट हो जाते हैं। सामान्यतः कीट व्याधियों व खरपतवारों से 50-60 प्रतिशत फसलोत्पादन की कमी आ जाती है क्योंकि फसलों में कीड़ों द्वारा 18-20 प्रतिशत, बीमारियों एवं रोगों के द्वारा 30-35 प्रतिशत तक खरपतवारों द्वारा 20-40 प्रतिशत तक नुकसान होता है। इनके नियंत्रण हेतु कृषकों को रासायनिक दवाओं का छिड़काव करना पड़ता है। जिससे समय, श्रम व लागत अधिक लगती है साथ ही भूमि को नुकसान भी होता है, व कृषि लागत भी बढ़ती है। अतः कम लागत में सुरक्षित खेती हेतु ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई एक सस्ता व कारगर कृषि उपाय है।

विधि -
रबी फसल की कटाई के तुरंत बाद खाली खेतों में मिट्टी पलटने वाले हल से (मोल्ड बोर्ड प्लाऊ) द्वारा 9-12 इंच तक गहरी जुताई करके छोड़ देते हैं। खेतों में फसलों की बुवाई के समय बार-बार एक निश्चित पर 6-7 इंच बखर या हेरो चलाने से खेतों में नीचे एक कड़ी परत बन जाती है जिससे वर्षा का संपूर्ण पानी खेतों द्वारा नहीं सोखा जाता है जिससे पानी खेतों से बाहर निकल जाता है और अपने साथ मिट्टी और फसलों के लिये आवश्यक पोषक तत्वों को बहा ले जाता है। ग्रीष्मकालीन जुताई 9-12 इंच तक मिट्टी पलटने वाले हल से करने पर यह कड़ी परत टूट जाती है और बरसात का पानी खेतों द्वारा अधिक मात्रा में सोख लिया जाता है मिट्टी धूप तपने से भुरभुरी

खेतों में फसलों की बुवाई के समय बार-बार एक निश्चित पर 6-7 इंच बखर या हेरो चलाने से खेतों में नीचे एक कड़ी परत बन जाती है जिससे वर्षा का संपूर्ण पानी खेतों द्वारा नहीं सोखा जाता है जिससे पानी खेतों से बाहर निकल जाता है और अपने साथ मिट्टी और फसलों के लिये आवश्यक पोषक तत्वों को बहा ले जाता है।

कालीन जुताई से रबी फसल की कटाई के बाद खाली खेतों की गहरी जुताई हो जाने से ये रोगजनक कीड़े भूमि के ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। सूर्य की तपन से सूखकर नष्ट हो जाते हैं।

(3) मृदा उर्वरता में वृद्धि -
पृथ्वी पर पाये जाने वाले वायुमण्डल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस होती है जो कि फसलों के लिये अमोनिया रूप से नत्रजन उपलब्ध कराती है। विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के कारण यह गैस वर्षा के जल में घुल जाती है जब पहली

ग्रीष्म कालीन गहरी जुताई: सुरक्षित खेती का आसान उपाय



हो जाती है और मिट्टी में वायु

बर सात होती है तब उसमें नत्रजन की अधिक मात्रा होती है। जो

फसलों के लिये आवश्यक है। खेत गहरे जुते होने पर यह वर्षा का संपूर्ण पानी खेतों द्वारा सोख लिया जाता है जो खेतों की उर्वरता में वृद्धि एवं जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। जिससे मृदा कटाव से खेतों को बचाया जा सकता है। साथ ही मिट्टी के साथ पोषक तत्वों को बहने से बचाया जा सकता है।

(4) जल संरक्षण

अधिकांशतः किसान भाई

फसलों की आवश्यकता के अनुसार एक निश्चित गहराई पर 6-7 इंच तक जुताई करते हैं। जिससे इस गहराई के नीचे मिट्टी की एक कड़ी परत बन जाती है। जिसके कारण खेतों में जल को सोखने में बाधा उत्पन्न होती है। अतः अप्रैल मई महिनों में गहरी जुताई (9 इंच से गहरी) करने से यह कड़ी सतह टूट जाती है जिससे वर्षा का संपूर्ण पानी खेतों द्वारा सोख लिया जाता है। जिससे जल स्तर बढ़ जाता है।

ध्यान रखने योग्य बातें -

(1) रबी फसल की कटाई हो जाने के तुरंत बाद खेतों में पर्याप्त नमी रहती है। अतः तुरंत जुताई करें। विलंब से जुताई करने पर मिट्टी सूर्य की तेज धूप में कड़ी हो जायेगी जिससे गहरी एवं अच्छी जुताई नहीं होगी।

(2) खेतों की जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें ताकि मिट्टी बड़े बड़े ढेलों के रूप में रहे जिससे गर्म लू जमीन में गहराई तक जा कर रोगजनकों एवं कीटों की शंखी अवस्था आदि को नष्ट कर दें।

(3) ग्रीष्म कालीन जुताई प्रत्येक वर्ष खेत में करें। यह आवश्यक नहीं है इसके लिये खेतों को 3 हिस्सों में बांट कर प्रत्येक वर्ष एक हिस्से की गहरी जुताई करें। इस प्रकार हर तीन वर्ष के अंतराल में प्रत्येक खेत की जुताई की जा सकती है। जुताई करते समय खेतों के चारों ओर मेढ़ बांधना आवश्यक है। जिससे वर्षा का पानी खेतों के बाहर नहीं जा सकेगा और पानी को जमीन सोख लेगी और खेती की उर्वरता बरकरार रहेगी।

क। संचार बढ़ जाता है और खेतों में जलधारण क्षमता बढ़ जाती है।

ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई के लाभ

(1) खरपतवार नियंत्रण -

फसलों के लिये खरपतवार एक बड़ी समस्या है कभी कभी इनके कारण 20 से

श्रीमती गीता सिंह

विषय वस्तुविशेषज्ञ (कृषि विस्तार)

कृषि विज्ञान केन्द्र, डिण्डौरी (म.प्र.)

श्री चन्द्रशेखर सिंह

(परियोजना अधिकारी)

जिला पंचायत डिण्डौरी (म.प्र.)

40 प्रतिशत तक उत्पादन कम हो जाता है। कुछ ऐसे खरपतवार हैं जैसे-कांस, मौथा, दूब, इनकी जड़े भूमि में काफी गहराई तक चली जाती है। जिनका नियंत्रण निंदाई, गुड़ाई व खरपतवार नाशी रसायनों से पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। गहरी जुताई से इनके राईजोम व जड़े बाहर निकल आती हैं अधिक धूप से सूखकर नष्ट हो जाते हैं।

(2) कीट-व्याधी नियंत्रण -

रबी की फसलों को हानि पहुंचाने वाले रोग के रोजजनक, रोगाणु हानिकारक कीड़े फसल की कटाई के बाद खेतों में ही मिट्टी की दरारों में सुसुसावस्था में पड़े रहते हैं और जब अगली फसल बोई जाती है तो रोजजनक रोगाणु कीड़े सक्रिय होकर फसलों को हानि पहुंचाना प्रारंभ कर देते हैं। कभी कभी इन रोगाणुओं एवं कीटों के कारण संपूर्ण फसल नष्ट हो जाती है। ग्रीष्म

खेती में पशुपालन एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में हमेशा से उपयोगी रहा है। सूखे के क्षेत्र में इसका महत्व और बढ़ जाता है और उसमें भी बकरी पालन सूखे की दृष्टिकोण व छोटे किसानों के लिहाज से काफी प्रभावी है क्योंकि इसमें लागत कम होने के साथ ही साथ आजीविका के विकल्प भी बढ़ जाते हैं।

परिचय

खेती और पशु दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। उत्तर प्रदेश की आजीविका इन्हीं दो के इर्द-गिर्द अधिकांशतः घूमती रहती है। खेती कम होने की दशा में लोगों की आजीविका का मुख्य साधन पशुपालन हो जाता है। गरीब की गाय के नाम से मशहूर बकरी हमेशा ही आजीविका के सुरक्षित स्रोत के रूप में पहचानी जाती रही है। बकरी छोटा जानवर होने के कारण इसके रख-रखाव का खर्च भी न्यूनतम होता है। सूखे के दौरान भी इसके खाने का इंतजाम आसानी से हो सकता है, इसके साज-संभाल का कार्य महिलाएं एवं बच्चे भी कर सकते हैं और साथ ही आवश्यकता पड़ने पर इसे आसानी से बेचकर अपनी जरूरत भी पूरी की जा सकती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में अधिकतर लघु एवं सीमांत किसान होने के कारण यहां पर सभी परिवार एक या दो जानवर अवश्य पालते हैं, ताकि उनके लिए दूध की व्यवस्था होती रहे। इनमें गाय, भैंस, बकरी आदि होती हैं। विगत कुछ वर्षों से पड़ रहे सूखे की वजह से और बड़े जानवरों के लिए चारा आदि की व्यवस्था करना एक मुश्किल कार्य होने के कारण लोग बकरी पालन को अधिक तरजीह दे रहे हैं। जंगल एवं बीहड़ के किनारे बसे गाँवों के लिए यह एक उपयुक्त एवं आसानी से हो सकने वाली आजीविका है, क्योंकि जंगलों में चराकर ही इनको पाला जा सकता है और गरीब परिवारों की रोजी-रोटी आसानी से चल सकती है। इस प्रकार बकरी पालन सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए एक मुफीद स्रोत है।

नस्लें

वैसे तो बकरी की जमुनापारी, बरबरी एवं ब्लेक बंगाल इत्यादि नस्लें होती हैं। लेकिन यहां पर लोग सूखा की स्थिति में देशी एवं बरबरी नस्ल की बकरियों का पालन करते हैं, जिनकी देख-रेख आसानी से हो जाती है।

प्रक्रिया

बकरी को पालने के लिए अलग से किसी आश्रय स्थल की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्हें अपने घर पर ही रखते

यह उल्लेखनीय है कि देशी बकरियों के अलावा यदि बरबरी, जमुनापारी इत्यादि नस्ल की बकरियां होंगी तो उनके लिए दाना, भूसी, चारा की व्यवस्था करनी पड़ती है, पर वह भी सस्ते में हो जाता है। दो से पांच बकरी तक एक परिवार बिना किसी अतिरिक्त व्यवस्था के आसानी से पाल लेता है। घर की महिलाएं बकरी की देख-रेख करती हैं और खाने के बाद बच्चे जूठन से इनके भूसा की सानी कर दी जाती है। ऊपर से थोड़ा बेझर का

बच्चे को एक वर्ष तक पालने के बाद ही बेचते हैं।

बकरियों में प्रमुख रोग

देशी बकरियों में मुख्यतः मुंहपका, खुरपका, पेट के कीड़ों के साथ-साथ खुजली की बीमारियाँ होती हैं। ये बीमारियाँ प्रायः बरसात के मौसम में होती हैं।

उपचार

बकरियों में रोग का प्रसार आसानी से और तेजी से होता है। अतः रोग के लक्षण

आने लगते हैं।

बकरी के छोटे बच्चों को कुत्तों से बचाकर रखना पड़ता है।

बकरी एक ऐसा जानवर है, जो फसलों को अधिक नुकसान पहुँचाती है। इसलिए खेत में फसल होने की स्थिति में विशेष रखवाली करनी पड़ती है। वरना खेत खाने के चक्र में आपसी दुश्मनी भी बढ़ने लगती है।

बकरी पालन में समस्याएं

हालांकि बकरी गरीब की गाय होती है, फिर भी इसके पालन में कई दिक्कतें भी आती हैं -

बरसात के मौसम में बकरी की देख-भाल करना सबसे कठिन होता है। क्योंकि बकरी गीले स्थान पर बैठती नहीं है और उसी समय इनमें रोग भी बहुत अधिक होता है।

बकरी का दूध पौष्टिक होने के बावजूद उसमें महक आने के कारण कोई उसे खरीदना नहीं चाहता। इसलिए उसका कोई मूल्य नहीं मिल पाता है।

बकरी को रोजाना चराने के लिए ले जाना पड़ता है। इसलिए एक व्यक्ति को उसी की देख-रेख के लिए रहना पड़ता है।

फायदे

सूखा प्रभावित क्षेत्र में खेती के साथ आसानी से किया जा सकने वाला यह एक कम लागत का अच्छा व्यवसाय है, जिससे मोटे तौर पर निम्न लाभ होते हैं-

जरूरत के समय बकरियों को बेचकर आसानी से नकद पैसा प्राप्त किया जा सकता है।

इस व्यवसाय को करने के लिए किसी प्रकार के तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती।

यह व्यवसाय बहुत तेजी से फैलता है। इसलिए यह व्यवसाय कम लागत में अधिक मुनाफा देना वाला है।

इनके लिए बाजार स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध है। अधिकतर व्यवसायी गांव से ही आकर बकरी-बकरे को खरीदकर ले जाते हैं।



बकरी पालन: सूखे में आजीविका का सहारा

हैं। बड़े पैमाने पर यदि बकरी पालन का कार्य किया जाए, तब उसके लिए अलग से बाड़ा बनाने की आवश्यकता पड़ती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में अधिकतर लोग खेती किसानों के साथ बकरी पालन का कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में ये बकरियां खेतों और जंगलों में घूम-फिर कर अपना भोजन आसानी से प्राप्त कर लेती हैं। अतः इनके लिए अलग से दाना-भूसा आदि की व्यवस्था बहुत न्यून मात्रा में करनी पड़ती है।

दाना मिलाने से इनका खाना स्वादिष्ट हो जाता है। बकरियों के रहने के लिए साफ-सुथरी एवं सूखी जगह की आवश्यकता होती है।

प्रजनन क्षमता

एक बकरी लगभग डेढ़ वर्ष की अवस्था में बच्चा देने की स्थिति में आ जाती है और 6-7 माह में बच्चा देती है। प्रायः एक बकरी एक बार में दो से तीन बच्चा देती है और एक साल में दो बार बच्चा देने से इनकी संख्या में वृद्धि होती है।

दिखते ही इन्हें तुरंत पशु डाक्टर से दिखाना चाहिए। कभी-कभी देशी उपचार से भी रोग ठीक हो जाते हैं।

बकरी पालन हेतु सावधानियां

बीहड़ क्षेत्र में बकरी पालन करते समय निम्न सावधानियां बरतनी पड़ती हैं- आबादी क्षेत्र जंगल से सटे होने के कारण जंगली जानवरों का भय बना रहता है, क्योंकि बकरी जिस जगह पर रहती है, वहां उसकी महक आती है और उस महक को सूंघकर जंगली जानवर गांव की तरफ

भैंस को आहार खिलाते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए की वह आहार किस उद्देश्य के लिए दिया जा रहा है तथा भैंस के शरीर में वह आहार कहाँ और कैसे उपयोग में आता है। इस आहार पर आहार/राशन को हम निम्नलिखित भागों में बाँट सकते हैं।

- जीवन निर्वाह आहार(1)
- बढ़वार आहार(2)
- गर्भावस्था आहार(3)
- उत्पादकता आहार(4)

जीवन निर्वाह आहार - चारे तथा दाने की वह कम से कम मात्रा जो पशु की आवश्यक जीवन क्रियाओं के लिए जरूरी होती है जिससे पशु विशेष के वजन में न तो कमी आये न ही वृद्धि हो, जीवन निर्वाह आहार कहलाती है। जीवन निर्वाह आहार की मात्रा पशु के वजन पर निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में अधिक वजन वाले पशु को जीवन निर्वाह के लिए अधिक आहार की आवश्यकता पड़ती है। चारे के अतिरिक्त एक वयस्क भैंस को लगभग एक से दो किलोग्राम दाना मिश्रण जीवन निर्वाह आहार के रूप में दिया जाता है। बढ़वार आहार - चारे व दाने की वह मात्रा जो



छोटे बच्चों की शारीरिक वृद्धि कर उनका वजन बढ़ाने में खर्च होती है, बढ़वार राशन कहलाती है। इसे जीवन निर्वाह आहार के अतिरिक्त दिया जाता है। बढ़ते हुए कटड़े/कटड़ियों को उग्र के अनुसार आधा किलो से दो

किलो तक दाना मिश्रण चारे के अतिरिक्त खिलाया जाता है। गर्भावस्था आहार - पशु के सात महीने से अधिक

भैंस : अवस्थाएं और आहार की आवश्यकता

की गाभिन होने पर उसे जीवन निर्वाह के अतिरिक्त गर्भावस्था में बच्चे के विकास तथा स्वयं को प्रसूतिकाल और उसके बाद स्वस्थ रखने के लिए जिस अतिरिक्त राशन की आवश्यकता होती है उसे गर्भावस्था आहार कहते हैं। भैंस को चारे की गुणवत्ता और गर्भाधान के दिन के आधार पर आठवें महीने से 1 से 2 किलोग्राम दाना मिश्रण अवश्य दिया जाता है।

उत्पादकता आहार - जीवन निर्वाह आहार के अतिरिक्त जो राशन दूध उत्पादन के लिए दिया जाता है, वह उत्पादकता आहार कहलाता है। उत्पादकता आहार की मात्रा भैंस द्वारा दिये जाने वाले दूध पर निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में अधिक दूध देने वाली भैंस को अधिक उत्पादकता आहार दिया जाता है। भैंस को प्रत्येक

दो किलोग्राम दूध पर (6 से 7 कि०ग्रा० प्रतिदिन दूध होने पर) एक किलोग्राम दाना मिश्रण की आवश्यकता पड़ती है। यह भरपेट अच्छे चारे के अतिरिक्त होती है। भैंसों जो दूध नहीं देती, गाभिन नहीं हैं और बूढ़ी हो चली हैं, उन्हें केवल जीवन निर्वाह के लिए ही आहार की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत जिस कटड़ी ने पहली बार बच्चा दिया है तथा फिर गाभिन भी हो गई है, उसे सबसे अधिक आहार की जरूरत पड़ती है। प्रजनन की सबसे अधिक समस्याएँ इन्हीं भैंसों में देखने को मिलती हैं क्योंकि इन्हें जीवन निर्वाह व उत्पादकता आहार के अतिरिक्त शरीर की बढ़वार के लिए भी पोषण की आवश्यकता होती है। यदि ब्याने के बाद भैंस का वजन तेजी से घटता है तो यह इस बात का प्रतीक है कि उसे आवश्यकतानुसार आहार नहीं मिल पा रहा है। प्रारम्भ में भैंस अपने अन्दर भंडारित ऊर्जा स्रोत वसा को प्रयोग में लाती है। उसके समाप्त होने पर वह अपने अंदर के प्रोटीन को प्रयोग में लाती है। तब भी आवश्यकतानुसार राशन नहीं मिलने पर उसका उत्पादन व बढ़वार दोनों बुरी तरह प्रभावित होते हैं। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि प्रजनन के लिए शरीर को ऊर्जा तभी मिलती है जब जीवन निर्वाह, बढ़वार और उत्पादन के लिये आवश्यक पोषण पशु को ठीक प्रकार से मिल रहे हों।

मूंगफली एक तिलहन फसल है इसकी खेती मुख्यतः दाने के लिये की जाती है जो तेल निकालने हेतु या खाने के काम लिये जाते हैं। मूंगफली प्रोटीन का एक अच्छा वसस्ता साधन है। इसमें विटामिन बी-1, बी-2 एवं बी-3 थोड़ी-थोड़ी मात्रा में उपलब्ध होते हैं। मूंगफली के तेल से वनस्पति घी तैयार किया जाता है। मूंगफली को फसल चक्र में शामिल करने से भूमि की उपजाऊ बनती है। राजस्थान में मूंगफली की औसत पैदावार एवं उत्पादकता बहुत कम है। उत्पादकता बढ़ाने के लिये उन्नत किस्मों, उन्नत शस्य क्रियाओं एवं कीट रोगप्रबंधन कार्यों को उचित समय पर उचित तरीके से अपनाना जरूरी है।

उन्नत किस्मों:

मूंगफली कि किस्मों को प्रकृति के अनुसार तीन अलग-अलग प्रजातियों में बांटा गया है। हल्की मिट्टी के लिये फैलने एवं कम फैलने वाली तथा भारी मिट्टी के लिये नही फैलनेवाली (झूमका/गुच्छ रूप) किस्में हैं, जो भूमि के प्रकार के अनुसार बोने के काम में ली जाती हैं। कम फैलने वाली या फैलने वाली प्रजाति के पौधों की शाखाये फैल जाती हैं तथा मूंगफली दूर-दूर लगती है। जबकि झूमका प्रजाति की फलियां मुख्य जड़ के पास लगती हैं और इनका दाना गुलाबी या लाल रंग का होता है। इसकी पैदावार फैलने वाली प्रजाति से कम आती है, परंतु ये जल्दी पकती है। उपयुक्त किस्मों की विशेषताओं का विवरण निम्न प्रकार है।

एम 13:-विस्तारी पौधों वाली यह किस्म 140-150 दिन में पककर 12-15 क्विंटल प्रति हैक्टेयर उपज देती है। रेतीली एवं दोमट मिट्टी के लिये उपयुक्त इस किस्म में वर्षान होने पर इसे सिंचाई की आवश्यकता होती है। निर्यात के लिये अधिक उपयुक्त इस किस्म का दाना मोटा हल्का भूरा एवं इसमें तेल मात्रा 49 प्रतिशत होती है।

एच.एन.जी 10:-यह अर्द्ध विस्तारी किस्म, अच्छी वर्षा या जहां जीवन रक्षक सिंचाई जलकी उपलब्धता वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसकी पत्तियां गहरी हरी तथा पौधे मध्यम फैलाव वाले होते हैं। यह किस्म 125-130 दिन में पक कर लगभग 20 क्विंटल प्रति हैक्टेयर उपज देती है। इसकी फली में औसतन दो दाने होते हैं। इनमें तेल की मात्रा 50-51 प्रतिशत होती है।

जी. जी. 20:-यह एक अर्द्ध विस्तारी किस्म है जो 115 से 120 दिन में पक जाती है इसकी फली में सामान्यतया 2 से 3 दाने होते हैं। 100 दानों का वजन 42 ग्राम के लगभग तथा दानों में 48 प्रतिशत तेल होता है। इसकी औसतन उपज 25 से 30 क्विंटल होती है।

टी.जी. 37 ए:-यह एक गुच्छदार मध्यम ऊंचाई तथा सीधी बढ़ाने वाली किस्म है जो 120-125 दिन में पक कर लगभग 20 क्विंटल प्रति हैक्टेयर उपज देती है। इसके दाने गुलाबीरंग के होते हैं तथा इनमें 48 प्रतिशत तेल तथा 23 प्रतिशत प्रोटीन की

मात्रा होती है।

खेत की तैयारी: मूंगफली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में उपजाई जा सकती है। रेतीली दोमट एवं भारी मटियार दोमट भूमि में अलग-अलग जाति की मूंगफली बोई जाती है। एकबार मिट्टी पलटने वाले हल से तथा बाद में देशी हल से या हैरो से 2 से 3 बार खेत की जुताई करें, ताकि भूमि भुरभुरी हो जाये और इसके बाद पाटा च ल ।

क र



मूंगफली की उन्नत कृषि तकनीकी



से उपयोग करें।

बीज एवं बुवाई:

-झूमका किस्म का 100 किलो बीज (गिरी) प्रति हैक्टेयर बोयें। इन किस्मों में कतार से कतारकी दूरी 30 सेन्टीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 10-15 सेन्टीमीटर रखें।

-फैलने वाली किस्म का 60-80 किलो

बीज (गिरी) प्रति हैक्टेयर बोयें। इन किस्मों में कतारसे कतार की दूरी 40-50 सेन्टीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 10-15 सेन्टीमीटर रखें।

-मूंगफली की बुवाई का सही समय जून के प्रथम से दूसरे सप्ताह तक है।

झूमका किस्मजून

के दूसरे पखवाड़े

में बोना फयदेमंद

पाया गया है।

सिंचाई एवं निराई गुड़ाई:

-सूखा पड़ने

इस रोग को शिखर विगलन (काउन रोट) भी कहते हैं। इस रोग का संक्रमण पौधों में किसी भी समय हो सकता है। तने के आधार तथा जड़ों के चारों तरफ अधिकतर काले बुरादे की परत जम जाती है। रोग से हानि पौधों की उम्र पर निर्भर करती है। रोग से हानि पौधों की उम्र पर निर्भर करती है। यदि रोग का प्रकोपबीज

डॉ. बी.एस. राठौड़,
आचार्य, कृषि अनुसंधान केन्द्र,
मण्डोर-जोधपुर 342304

के जमने के समय हो तो सम्पूर्ण फसल नष्ट हो जाती है तथा देरी से संक्रमण होने पर फलीयाँ नही बनती हैं और बनती भी है तो दाने सिकुड़े एवं हल्के उत्पन्न होते हैं।

स्तम्भमूल संधि विगलन रोग से ग्रसित मूंगफली

रोग से बचाव केलिये बीज को 2 ग्राम कार्बेन्डाजिम या कार्बोक्सि. थाईराम का मिश्रण 3 ग्राम या 10 ग्राम ट्राइकोडरमा

प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करे तथा बुवाई से पहले 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडरमा पाउडर को 100 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद में मिलाने के 15 दिन बाद कूड़ों में

डालें।



पर आवश्यकतानुसार 1-2 सिंचाई खासतौर पर फूल आने और दाना बनते समय आवश्यक करें। एक ही सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध हो तो इस सिंचाई को 55-75 दिनकी अवधि में दें।

-खेत में खरपतवार निकालते रहें। 30 दिन की फसल होने तक निराई गुड़ाई पूरी कर लेवें। बुवाई के एक माह झूमका किस्म के पौधों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ायें। जमीन में सुईयाबनना शुरू होने के बाद गुड़ाई बिल्कुल न करें।

-जहां निराई गुड़ाई मुश्किल हो वहां सिंचित फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु खेत में आखिरी जुताई से पूर्व एक किलो फ्लूक्लोरेलिन प्रति हैक्टेयर छिड़कें। ध्यान रहे कि रसायन जुताईके समय भूमि में मिल जायें। तत्पश्चात् मूंगफली की बुवाई कतारों में करें।

रोग एवं नियंत्रण:

स्तम्भमूल संधि विगलन (कोलर रोट):-

पत्ती धब्बा (टिक्का):- यह रोग एक ही कवक की दो विभिन्न जातियों द्वारा अलग अलग समय पर आक्रमण करने से होता है, जिसके अनुसार अगेती तथा पछेती टिक्का नाम से जाना जाता है, शुरू में पत्तियों पर भूरे-काले घब्बे बनते हैं, जो बाद में फैलकर पर्णवृत्त तथा तनोंको भी सपेट में ले लेते हैं।

इन धब्बों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है जिससे पत्तियाँ सूखकर गिरने लगती हैं। रोकथाम हेतु रोग दिखाई देते ही कार्बेन्डाजिम 1 ग्राम अथवा एक से डेढ़ग्राम मैन्कोजेब का प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव करें। इसके बाद 10-15 दिन के अन्तर पर ऐसे दो छिड़काव और करें।

पीलिया रोग:- इस रोग से पौधे पीले पड़ जाते हैं। नियंत्रण के लिये बुवाई से पूर्व 25 किलो हराकसीस प्रति हैक्टेयर भूमि में मिलावें तथा फसल की 45 व 60 दिन

की अवस्था पर हराकसीस का 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल का पर्णाय छिड़काव करें। इसके अभाव में गंधक के तेजाब के 0.1 प्रतिशत घोल का फसल में फूल आने से पहले एक बार तथा पूरे फूल आ जाने के बाद दूसरी बार छिड़काव करें। इस घोल में चिपकाना पदार्थ जैसे साबुन आदि अवश्य मिलावें।

कीट एवं नियंत्रण:

दीमक:- ये पौधों की जड़ों को काट देती है जिससे पौधे सूख कर मर जाते हैं। प्रायः दीमकरात्रि में सक्रिय रहती है। खड़ी फसल में दीमक का प्रकोप दिखाई देने पर 2 लीटरक्लोरोपायरीफॉस 20 ईसी प्रति हैक्टेयर सिंचाई के पानी के साथ दें। दीमक के जैविकनियंत्रण हेतु बुवाई से पहले 5 किलोग्राम बावेरिया बेसियाना पाउडर को 125 किलोग्राम गोबरकी सड़ी हुई खाद में मिलाने के 15 दिन बाद खेत में डालें।

कातरा:- कातरे के पतंगों को नियंत्रण करने के लिये गैस लालटेन या बिजली का बल्बजलाये तथा इनके नीचे मिट्टी के तेल मिले पानी की परत रखें ताकि रोशनी पर आकर्षितपतंगे पानी में गिर कर नष्ट हो जायें। खेत के मेड़ों पर उगे जंगली पौधों एवं फसल पर मिथाईल पैराथियोन 2 प्रतिशत या क्यूनालफॉस 1.5 प्रतिशत चूर्ण 25 किलो प्रति हैक्टेयर की दर से भुरकाव करें जिससे इसकी लटें नष्ट हो जाये। जहां पानी उपलब्ध हो वहां मिथाईल पैराथियोन 50 ईसी 750 मिलीलीटर या क्यूनालफॉस 25 ईसी 625 मिलीलीटर प्रति हैक्टेयरका छिड़काव करें।

मोयला:- इसे माहू या चैंपा भी कहते हैं। यह छोट-छोटे जीव पौधों के कोमल भागों से रस चूस कर उन्हें कमजोर बना देता है। इसके नियंत्रण हेतु मैलाथियोन 5 प्रतिशत या मिथाईल पैराथियोन 2 प्रतिशत चूर्ण 25 किलो प्रति हैक्टेयर की दर से भुरकाव करें या मैलाथियोन 50 ईसी सवालीटर या मिथाईल पैराथियोन 50 ईसी 750 मिलीलीटर या मिथाईल डिमेटॉन 25 ईसी 1 लीटर दवा का घोल बनाकर प्रति हैक्टेयर छिड़काव करें।

खुदाई: मूंगफली पकने का समय अक्टूबर अन्त से नवम्बर मध्य तक है। फसल पकते समयभी हरी रहती है अतः खोद कर देख लेवें कि फलियां पक गयी हैं या नहीं। अगर 80 प्रतिशत फलियां पक गई हो और पत्तियाँ पीली पड़ जाये तो खुदाई कर लेवें। फली तभी परिपक्व होती है जब वह सख्त और कड़ी हो जाती है, तथा भीतरी भाग खुरदुरा हो जाता है तथा उसपर नाडियों का जाल बिछ जाता है। खेत में सिंचाई करके अथवा बत्तर आने पर पौधे को उखाड़ लेवें। इन पौधों को ढेर के रूप में 7-10 दिन तक धूप में सुखाये और उसके बाद मूंगफली को तोड़कर अलग निकाल लेवें।

भण्डारण: मूंगफली को अच्छी तरह सुखाकर ही भण्डारण करें। मूंगफली के दानों में नमीकी मात्रा 8 से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये अन्यथा बीज पर एस्पेरजिलस नामफफ़ूंद लगने से एक विषैलापदार्थ (एफ्लाटोक्सिन) जमा होना शुरू हो जाता है। इससे ग्रस्तबीजों को खाना घातक सिद्ध होता है।

किसी भी फसल के लिए जल नितांत आवश्यक तत्त्व है। फसल की क्रांतिक अवस्थाओं में जल की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होती है तो पैदावार में निश्चित रूप से गिरावट आयेगी। अतः वर्षा ऋतु में जल को संग्रहित करना एवं उस संरक्षित जल का समय पर उपयोग करना अच्छी पैदावार के लिए अति आवश्यक है। जल संरक्षण के तरीके:-

1. भू समतलीकरण एवं मेढबंदी:-अधिक ढालू भूमियों का समतलीकरण किया जा सकता है। समतलीकरण करने से इन भूमियों के ऊपर से वर्षा जल के बहाव में रूकावट आयेगी एवं भूमि का खरण भी कम होगा। भूमि ढाल के प्रतिशत की अपेक्षा वर्षा जल दुगुनी गति से बहता है। अतः ढाल को जितना कम किया जायेगा भूमि पर पानी के बहाव की गति दुगुनी मात्रा में कम होगी। इस प्रकार ढलान की प्रतिशतता को कम करके भूमि कटाव को कम किया जा सकता है एवं भूमि में जल की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। यदि ढालू खेती का समतलीकरण किया गया है तो इन समतल खेतों के चखरों और मेढ बनाना चाहिए जिससे खेत का पानी एवं खेत की मिट्टी खेत में ही रहें।
2. ढाल के विपरीत दिशा में जुताई:- यदि खेतों में ढाल का प्रतिशत अधिक है तो ढाल की विपरीत दिशा में हल या अन्य उपलब्ध कृषि यंत्रों द्वारा खेतों की गहरी जुताई करना चाहिए। इससे वर्षा का पानी खेत में अधिक गहराई तक अवशोषित होगा एवं उसके नीचे की ओर बहने की गति कम होगी। अन्ततोगत्वा भूमि क्षरण की दर में कमी आयेगी। ढाल की विपरीत दिशा में जुताई करने से हल द्वारा निर्मित नालियों में पानी अधिक समय तक खेत में ठहरेगा जिससे भूमि में जल की प्रतिशतता मात्रा में वृद्धि होगी।
3. खेत के ऊँचे स्थान पर सोक पिट एवं बाँरो पिट का निर्माण:-ढाल खेतों के ऊँचे स्थानों समतल स्थान पर सोक पिट एवं बाँरो पिट का निर्माण किया जाता है। ये संरचनायें ऊँचे स्थान के पानी को नीचे नहीं बहने देती हैं एवं इन संरचनाओं के माध्यम से खेत का पानी खेत में अवशोषित होते रहता है जिससे मिट्टी का कटाव भी कम होता है। सोक पिट एवं बाँरो पिट छोटी-छोटी संरचनायें होती हैं अतः इनके निर्माण में अधिक खर्च नहीं आता है।
4. सम्मोच रेखाओं पर खेती का निर्माण:-अत्यधिक ढलान वाले खेत जिनको समतल करना आसान नहीं होता है वहाँ पर कंटूर ट्रेच (सम्मोच रेखाओं पर खेती) का निर्माण किया जाता है। इन खेतों के निचले हिस्से में फलदार वृक्षों का रोपण करना चाहिए। इस प्रकार की खन्तियों का निर्माण करने से खेत में अधिक पानी रूकता है एवं मृदा-कटाव में कमी आती है।
5. कंटूर पर स्टेगर्ड या कंटिन्यूअस ट्रेन्चेज बनाना:-सम्मोच रेखाओं पर असम्बद्ध खन्तियों का निर्माण किया जाता है। अत्यधिक ढालू भूमियों पर इन संरचनाओं का निर्माण करना महत्त्वपूर्ण एवं लाभप्रद कार्य है। स्टेगर्ड ट्रेन्चेज के

निचले हिस्से में जहाँ पर मिट्टी एकत्रित होती है वहाँ पर फलदार एवं बहुद्वेशीय वृक्षों के पौधों का रोपण किया जा सकता है। ढालू भूमियों पर इस विधि को अपनाने

है जिसे रिसन तालाब कहते हैं। इनका आकार छोटा होता है। इस तालाब की विशेषता यह होती है कि इसमें जो वर्षा जल एकत्रित होता है वह भूमि में रिसन

भू-जल अपरोक्ष रूप से फसल के लिए लाभकारी होता है।

ब. डबरी:-मध्य भूमि में निर्मित होने वाले तालाब को डबरी के रूप में पहचाना जाता

जल संरक्षण के लिए तालाब का निर्माण किया जाता है। क्योंकि यह निचली भूमियों में स्थित होता है। इसलिए इसमें वर्षा जली लम्बे समय तक संग्रहित रहता है। दूसरी फसल के लिए भी तालाब से पर्याप्त मात्रा में सिंचाई जल उपलब्ध होता है। तालाब निर्माण में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसमें जल प्रवेश एवं जल निकासी मार्ग अवश्य रूप से बना हुआ है। तालाब जल संरक्षण तकनीक की एक वृहद् संरचना होती है एवं उसकी जल धारण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी स्थिति में तालाब का पानी उसी मेढों से होकर न गुजरे अन्यथा तालाब के मेढ क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तालाब के मेढों के अन्दर की तरफ अगर हो सके तो काली मिट्टी का लेप लगाया या पत्थरों से मजबूती प्रदान करें ऐसा करने से मेढों की मिट्टी बहकर तालाब में जमा नहीं होगी एवं तालाब की जल संरक्षण संग्रहण क्षमता का हास नहीं होगा।

इन सब तकनीकों को अपनाकर किसान वर्षा जल का समुचित संग्रहण कर उचित समय पर उपयोग कर सकते हैं।

-डॉ. बी. एस. राठौड़

आचार्य एवं कृषि अनुसंधान केन्द्र, मण्डोर, जोधपुर



के निम्न फायदे हैं:

1. अधिक ढाल वाला भूखण्ड छोटे-छोटे हिस्सों में बँट जाता है एवं स्टेगर्ड ट्रेन्चेज (असम्बद्ध खन्ती) लघु जल संचयन तालाब का कार्य करती है।
2. खोदी गई मिट्टी को गड्डे के निचले हिस्से पर रखा जाता है जिससे भूमि में नमी बनी रहती है एवं पौधों को मिलती रहती है।
3. स्टेगर्ड या कंटिन्यूअस ट्रेन्चेज के निर्माण से वर्षा जल भूमि पर तीव्र गति से नहीं बहता है जिससे मिट्टी कटाव में कमी आती है एवं भूमि में जल का अधिक संचयन होता है।
4. ढालू पहाड़ियों एवं भूमि में इस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करने के पश्चात् वनस्पतिक अवरोध अथवा जो भी वृक्षारोपण किया जाता है उसकी तीव्र वृद्धि होती है व प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा होती है।
6. वनस्पतिक अवरोध/रोक (वेजीटेटिव बेरियर):-वनस्पतिक अवरोधों द्वारा मृदा-कटाव में रोक एवं नमी संरक्षणका कार्य आसानी से सस्ते में किया जा सकता है। इसके अन्तर्गत ढालू भूमियों में 10 मीटर या सुविधानुसार दूरियों पर घास या अन्य वनस्पतियों की बाढ़ लगायी जाती है जिससे बहने वाले जली की गति में रूकावट आती है जिससे भूमि का कटाव कम होता है एवं भूमि में नमी का अधिक संचयन होता है। यदि घास की बाढ़ बनायी गयी है तो घास को काटकर दुधारू जानवरों को खिलाया जा सकता है। अतः मृदा एवं जल संरक्षण के साथ-साथ पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी हो जाती है।
7. तालाबों का निर्माण:- अ. रिसन तालाब:-मरहान या टिकरा भूमि में जल संरक्षित रकने के लिए छोटी डबरी बनायी जाती

के द्वारा भू-जल की मात्रा को बढ़ जाती है क्योंकि यह तालाब ऊँचाई पर स्थित होता है इसलिए इसमें वर्षा जल अधिक समय तक उपलब्ध नहीं रहता परन्तु यह भूमि को नमी प्रदान कर भूमि की भू-जल मात्रा की वृद्धि करते हैं। यह

है। यह मध्यम आकार के होते हैं। वर्षा जल ऊँचाई से बहता हुआ इसमें एकत्रित होता है एवं लंबे समय तक इसमें संग्रहित रहता है। सिंचाई के लिए इससे जल लिया जाता है।

स. तालाब:-निचली भूमि या गभार में

सृष्टि एगो परिवार आपका स्वागत करता है

सदस्यता फार्म

सदस्य का नाम:.....
 संस्था का नाम:.....
 पूरा पता:.....
 ग्राम :.....तहसील :.....

जिला:.....राज्य:.....पिन कोड

दूरभाष कार्य:.....निवास:.....

सदस्यता राशि

एक वर्ष :151 तीन वर्ष :351 पांच वर्ष :501

कृपया हमें/मुझे सृष्टि एगो की सदस्यता प्रदान कर नियमित रूप से उक्त पते पर पत्रिका भेजने की व्यवस्था करें।

सदस्यता राशि नकद/मनीऑर्डर/चैक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा राशि रूपये (अंकों में) शब्दों में :.....

बैंक का नाम:..... ड्राफ्ट चेक क्रमांक:.....दिनांक:.....

स्थान:..... प्रतिनिधि का नाम:.....हस्ताक्षर सदस्य:.....

दिनांक:.....

सृष्टि एगो

ग्रामीण विकास का संपूर्ण पाक्षिक समाचार पत्र

307, लिंकवे इस्टेट, लिंक रोड, मालाड (पश्चिम), मुंबई - 400064. Tel: 022-66998360/61 Tel: 022-66998360/61.

Fax: 022-66450908. Email: info@srushtiagroneews.com, website: www.srushtiagroneews.com

एवं हस्ताक्षर

एवं संस्था सील

सैलेश मेहता एफएआई, पश्चिमी क्षेत्र के अध्यक्ष निर्वाचित



पुणे। सैलेश मेहता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमि कल्स कार्पोरेशन लि. को एफएआई के पश्चिमी क्षेत्र के अपनी 54वीं वार्षिक बैठक के दौरान अध्यक्ष रूप में वर्ष 2014-15 के लिए सर्व सम्मति मति से निर्वाचित किया गया।

एसोसिएशन के पश्चिमी क्षेत्र में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा राज्य सम्मिलित हैं। एफएआई के सभी सदस्यों ने इस प्रतिष्ठित पद के लिए निर्वाचित होने पर सैलेश मेहता को बधाई दी। सदस्यों को संबोधित करते हुए मेहता ने उर्वरक उद्योग

की समस्याओं को उचित स्तर पर उठाया जाएगा, यह आश्वासन दिया तथा उर्वरक के संतुलित उपयोग के माध्यम से बेहतर उत्पादकता हेतु किसान को केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

दि फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पश्चिमी क्षेत्र की वार्षिक बैठक अतानु चक्रवर्ती, आईएसएस, अध्यक्ष- एफएआई, पश्चिमी क्षेत्र और प्रबंध निदेशक, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि. की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में आर.जी. राजन, अध्यक्ष एफएआई, न्यू दिल्ली तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि., संबाशिव राव, प्रबंध निदेशक, कृषक भारती को. ऑपरेटिव लि. और डी.डी. खोसे, क्षेत्रीय कार्यकारी, एफएआई पश्चिमी क्षेत्र और उर्वरक उद्योग के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे। मेहता कृषि आदान व्यवसाय में कुशल नेतृत्व करने वाले उद्योजक माने जाते हैं।

चना उच्च अस्थिरता के साथ कारोबार

दिल्ली। मांग इन निचले स्तरों पर थोड़ा गुलाब के रूप में चना उच्च अस्थिरता के साथ कारोबार किया। ट्रेडर्स चुनाव खत्म और मिलता है कि कुछ हद तक कीमतों का समर्थन कर सकता के रूप में आने वाले दिनों में बढ़ती शुरू करने की मांग की आशा। आईएमडी ने पूर्व रूप में कमजोर मानसून की खबरें पिछले सप्ताह लेकिन चुनाव दरों को दृढ़ किया था और रुकना तम्बू छुट्टियों मांग कम रखा है।

मिलर्स से मजबूत मांग के अभाव के बीच खराब गुणवत्ता पहुँचने हाल के सप्ताहों में चना के लिए कीमतों में गिरावट रखते हुए



किया गया है। लेकिन दरों के साथ हवलदार आईएनजी एक बहुत गिर गया है, घरेलू मांग चुनाव खत्म होने के एक बार में वृद्धि की संभावना है। ऑस्ट्रेलियाई चना उत्पादन रिपोर्ट 4 23 प्रतिशत से गिर गया है। (डॉलर पुन बनाम कमजोर शेष के साथ) कम दामों पर महत्वपूर्ण आयात के किसी भी मजबूत पूर्व दिए गए हैं। कृषि को फिर से बंदरगाहों के मंत्रालय के अनुसार, रबी दलहन के लिए बुवाई क्षेत्र एक उच्च रिकॉर्ड 16.2 करोड़ होने का अनुमान है।

900 ऊपर ले जाने के लिए उपज में महत्वपूर्ण सुधार की वजह से अनुकूल मौसम के लिए भी संभव था। भारत सरकार ने रुपए के लिए विपणन वर्ष 2014-15 के लिए चना के लिए एमएसपी उठाया. 3100 / क्यू - अप रुपय। पिछले साल की कीमतों की तुलना में 100। इस क्षेत्र बुवाई में वृद्धि सक्षम होना चाहिए. म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से दालों का आयात वृद्धि हो रही है. काबुली चना का आयात कर रहे हैं। पुन बनाम डॉलर में गिरावट दलहन दरों शो आईएनजी कुछ सुधार सुनिश्चित करना है जो, हालांकि कम आयात लागत को रखा गया है।

सोयाबीन में 2014-15 में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई

दिल्ली। मेरा 2014-15 में 1.6 मिलियन हेक्टेयर में 17 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है यूक्रेन में किसानों अन्य फसलों की तुलना में सोयाबीन से बेहतर रिटर्न प्राप्त हुआ है और वे सोयाबीन के तहत प्रारंभिक अनुमान क्षेत्र के प्रति मेरी 2014 15. ह्य में सोयाबीन के तहत कवरेज क्षेत्र बढ़ाने की योजना बनाई है 1.36 मिलियन हेक्टेयर पिछले साल खिलाफ. औसत उपज के आधार पर उत्पादन एमएमटी हद्द 3.2 सकता है. ग्लोबल सोयाबीन बाजार सोया किसानों के लिए आकर्षक बना हुआ है. सोया उत्पादों के लिए समग्र दृष्टिकोण भी घरेलू बाजार में भोजन, तेल के लिए अच्छी मांग है मुख्य रूप से इस तिलहन के निर्यात आकर्षण से प्रेरित है. इसके अलावा, घरेलू सोयाबीन उत्पादन देश में औद्योगिक पोल्ट्री और पशु उत्पादन बढ़ने से घरेलू मांग का जवाब देने के लिए जारी की उम्मीद है.

चावल की खरीद -2013-14 में 26 लाख टन छुआ

दिल्ली। चावल की अखिल भारतीय प्रगतिशील खरीद पिछले वर्ष इसी अवधि से 30,890,000 टन की खरीद के खिलाफ बारे में 26,620,000 टन है. पंजाब (8.10 लाख टन) से सर्वोच्च खरीद योगदान आंध्र प्रदेश (4.33 लाख टन) और छत्तीसगढ़ (4.28 लाख टन) द्वारा पीछा किया. 2012-13 में कुल खरीद 34,020,000 टन है.

1360 के लिए 1365 प्रति टन में केस्टर के लिए एफओबी उद्धरण

दिल्ली। नकदी बाजार में वृद्धि की खरीद और फर्म को उच्च कारण केस्टर बीज नकदी बाजार ट्रेडों पिछले ऑपरेटर्स से उच्च कारोबार सक्रिय हैं और मौजूदा स्तर से आगे यह ऊपर की कीमतों को खींच सकता है. अरंडी के बीज की आवक लगभग 1 लाख बैग (80 किलो) को 1.10 लाख बैग से थोड़ा कम है. यह चक्र प्रति 3850 रुपये 3700 में कार्रवाई में बेचा जा रहा है. और व्यापारी इस स्तर से किसी भी दबाव तेल के लिए एफओबी उद्धरण सक्रिय हैं और इस महीने निर्यात आंकड़ा 50,000 टन को पार कर सकते खरीदारों प्रति . 1360 के लिए . 1365 सप्ताह में कम करने के लिए जारी रहेगा है

सऊदी अरब में भारतीय हरी मिर्च का तड़का

दिल्ली। भारतीय हरी मिर्च में कीटनाशकों की मात्रा ज्यादा होने की वजह से सऊदी अरब ने भारत से हरी मिर्च के आयात पर रोक लगा दी है। प्रतिबंध 30 मई से लागू होगा। सऊदी अरब भारत से ताजी सब्जियों का पांचवां बड़ा आयातक है, लेकिन गुंटूर के मिर्च व्यापारी शिव कुमार के मुताबिक भारत हरी मिर्च का ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता है, जिसके कारण भाव पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।



भारतीय दूतावास में राजनीति और वाणिज्य के द्वितीय सचिव सुरेंद्र भगत ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हरी मिर्च के आयात

पर रोक लगाने के संबंध में हमें सऊदी कृषि मंत्रालय ने अवगत कराया है। हम सऊदी अधिकारियों के संपर्क में हैं। सऊदी कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, हरी मिर्च के आयात पर रोक का फैसला भारतीय शिपमेंट के एक नमूने की जांच के बाद लिया गया है।

MANUFACTURER AND BULK SUPPLIER OF FERTILIZERS PRODUCTS

UDIT OVERSEAS PVT. LTD.

137, INDUSTRIAL AREA DEHRA, TEHSIL-CHOMU, DISTT. JAIPUR

Products Range:-

- ◆ Micronutrients
- ◆ Mixture
- ◆ Secondary Nutrients
- ◆ Growth Promoters
- ◆ Bio Stimulants
- ◆ Bio Fungicide
- ◆ Bio Insecticide
- ◆ Bactericide
- ◆ Wetting Agent
- ◆ Zyme
- ◆ Tonic

WE WELCOME YOUR INQUIRY

CONTACT DETAIL

MR. ALOK BENIWAL

MOB: 9660258447

एग्री मिन धान, कपास और अरहर में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि का प्रस्ताव



दिल्ली। कृषि मंत्रालय रुपए पर 50 रुपए 2014-15 फसल वर्ष के लिए 1360/ (जुलाई से जून) के द्वारा और रुपये 100 तक धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में एक उदारवादी वृद्धि का प्रस्ताव किया है दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ा. मंत्रालय ने एक रुपये 50 प्रति क्विंटल मध्यम प्रधान के लिए रुपये 3750 में कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है और 2014-15 फसल वर्ष के लिए लंबे समय से प्रधान के लिए रुपये 4050 का प्रस्ताव किया है, सूत्रों ने कहा. धान, कपास और अन्य 12 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि मंत्रालय की सिफारिशों को कृषि लागत और मूल्य (सीएसीपी) के लिए सरकार की सांविधिक निकाय आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के साथ लाइन में हैं, सूत्रों ने कहा. एक कैबिनेट नोट अंतर - मंत्रालयी टिप्पणी के लिए ले जाया गया है. एमएसपी प्रस्ताव पर अंतिम फैसला नई सरकार द्वारा पद के चुनाव में लिया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक, कृषि मंत्रालय रुपए पर 50 रुपए से धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि का प्रस्ताव किया है 2014-15 के

लिए धान का ग्रेड ए किस्म के लिए 1400 क्विंटल रुपये के लिए आम विविधता और 55 रुपये बढ़ाने के एक उठाने के लिए 1360 क्विंटल फसल वर्ष. धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में एक उदारवादी वृद्धि देखने सरकारी गोदामों में चावल की अत्यधिक स्टॉक में रखने की सिफारिश की गई है, सूत्रों ने कहा. अन्य अनाजों के संबंध में, मंत्रालय संकर किस्म के लिए रुपये 1530 क्विंटल में 30 रुपए से मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य में मामूली वृद्धि का सुझाव दिया है और इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य दो साल पहले तेजी से उठाया गया था के रूप में रुपये इस वर्ष के लिए किस्म के लिए 1550 क्विंटल. इसी प्रकार, यह पिछले साल भर से 2014-15 के लिए रुपये 1550 क्विंटल पर रागी न्यूनतम समर्थन मूल्य में एक रुपये 50 उठाना सुझाव दिया गया है. हालांकि, मंत्रालय ने 2014-15 फसल वर्ष के लिए क्रमशः मौजूदा रुपये 1250 क्विंटल में बाजरा और मक्का के न्यूनतम समर्थन मूल्य और रुपये 1310 क्विंटल, बनाए रखने की सिफारिश की है. यह भी क्रमशः रु 4000 क्विंटल और रुपये 2500-2560 क्विंटल में इस वर्ष के

लिए मूंगफली और अपरिवर्तित सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य रखने का प्रस्ताव किया है. जहां तक दालों का सवाल है, कृषि मंत्रालय रुपये पर अरहर और उरद के समर्थन मूल्य में 50 रुपये की बढ़ोतरी की सिफारिश की है 2014-15 के लिए प्रत्येक 4350 क्विंटल. मंत्रालय खरीफ (गर्मी) दालों के भीतर अंतर - फसल समता रखने के लिए इस वर्ष के लिए प्रति क्विंटल 4600 में मूंगब का न्यूनतम समर्थन मूल्य में एक रुपये 100 वृद्धि की सिफारिश की है. तिलहन के संबंध में, मंत्रालय मूंगफली और 2014-15 के लिए अपरिवर्तित सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य रखने का प्रस्ताव किया है. हालांकि, इसके लिए, क्रमशः 4600 में तिल और न्यूनतम समर्थन मूल्य में 100 रुपये की बढ़ोतरी प्रत्येक और रुपये 3600 क्विंटल, इसके अलावा पिछले साल भर से रुपये 3750 क्विंटल पर सूरजमुखी के बीज का समर्थन मूल्य में 50 रुपये की वृद्धि का सुझाव दिया गया है इस साल. खरीफ में बुआई (गर्मियों) के मौसम के दक्षिण पश्चिम जून से मानसून और कटाई की शुरुआत के साथ शुरू होता अक्टूबर से शुरू होगा.

गेहूं की खरीद पिछले साल के 25 एम.एन. टन के स्तर से नीचे आने की संभावना

दिल्ली। चल रहे 2014-15 विपणन वर्ष के लिए सरकार की गेहूं खरीद के लक्ष्य चूक गए और 25 लाख टन के पिछले साल के स्तर से नीचे पचीं होने की संभावना है, खाद्य सचिव ने कहा कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की खाद्य निगम (एफसीआई) ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मिल सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से अनाज खरीद चलाती है. खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार के स्वामित्व वाली एजेंसियों साल पहले की अवधि में खरीदा 11,960,000 टन की तुलना में काफी कम है, इस साल अब तक गेहूं की 7.5 करोड़ टन की खरीद की है. गेहूं विपणन वर्ष अप्रैल से मार्च तक चलता है, लेकिन एफसीआई की खरीद आपरेशन तीन महीनों में पूरा हो जाता है. आटा पिसाई उद्योग के मुद्दों पर एक सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा, पिछले साल भारतीय खाद्य निगम के गेहूं के 25 लाख टन खरीद की थी. मेरे अपने आकलन के अनुसार, इस वर्ष के कुल गेहूं की खरीद पिछले साल की तुलना में कम हो जाएगा, 'कुमार ने कहा. हालांकि, गेहूं खरीद सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और दोपहर का भोजन की तरह अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के तहत मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा, उन्होंने कहा. कुल मिलाकर गेहूं खरीद चालू वर्ष के लिए निर्धारित 31 लाख टन के लक्ष्य की तुलना में काफी कम होने की उम्मीद है. खाद्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, पंजाब में गेहूं की खरीद की गति हाल बिन मौसम की बारिश के बाद, की वजह से



राज्य में देरी हो रही कटाई के लिए बहुत धीमी है. एफसीआई के रूप में पिछले वर्ष इसी अवधि में 4.3 करोड़ टन की तुलना, मौजूदा विपणन वर्ष में आज की स्थिति के अनुसार पंजाब में 9,40,581 टन की खरीद करने में सक्षम हो गया है, सरकारी आंकड़ों कहते हैं. पंजाब में कई क्षेत्रों में गेहूं उत्पादकों भी उच्च नमी सामग्री का हवाला देते हुए खरीद एजेंसियों द्वारा फसल की गैर सरकारी खरीद की शिकायत की है. मध्य प्रदेश में सरकारी खरीद भी समीक्षा अवधि में 3.6 लाख टन की तुलना में 31.7 लाख टन कम है, जबकि हरियाणा में गेहूं की खरीद, 3.7 मिलियन टन की तुलना में 3.2 करोड़ टन सीमांत रूप से नीचे है. राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अन्य से बढ़ राज्यों में खरीद पिछले साल के स्तर के पीछे पीछे चल रही है. भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, में गेहूं का उत्पादन एक साल पहले की अवधि में 93,510,000 टन की तुलना में इस वर्ष के लिए 95600000 टन रहने का अनुमान लगाया है. इस तरह के उत्पादों का समर्थन करने के लिए सरकार पर, उद्योग आगे आते हैं और सुरक्षित उत्पादों के लिए एक बाजार बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए, 'कुमार गेहूं के बारे में चिंताओं को और बढ़ावा देने और पता करने के लिए एक राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना के लिए आटा पिसाई उद्योग के सुझाव पर. कहा अपने देश में उत्पादों, कुमार एक अलग परिषद की आवश्यकता है और यह खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के तहत स्थापित किया जा सकता है, 'कहा. मैं चिंतित सचिव के साथ इस प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे.

2014/04/30 तक चीनी उत्पादन

दिल्ली। 30 अप्रैल 2014 तक चीनी के बारे में 237.5 लाख टन की इसी अवधि के दौरान पिछले साल चीनी का उत्पादन 246 लाख टन के खिलाफ उत्पादन किया गया है. चीनी मौसम 2013-14 में लगभग केवल बारे में 80 चीनी मिलों को 30 अप्रैल 2014 पर संचालन के साथ समाप्त हो गया है. जमहाराष्ट्र चीनी की रिकवरी के 11.4% के साथ चीनी की 671 लाख टन पेराई के बाद चीनी की 76.50 लाख टन का उत्पादन किया गया. 30 अप्रैल 2014 की स्थिति के अनुसार, केवल 15 मिलों अभी भी गन्ना पेराई गया. इसी अवधि के दौरान पिछले साल चीनी का उत्पादन चालू वर्ष के रूप में ही चीनी की रिकवरी के साथ 79.81 लाख टन पर था. अभी भी काम कर रहे हैं जो 15 कारखानों ज्यादातर कोल्हापुर और पुणे क्षेत्र में स्थित हैं. उत्तर प्रदेश शुगर वसूली के 9.27% के साथ चीनी के बारे में 64.10 लाख टन का उत्पादन करने के लिए गन्ने का 692 लाख टन कुचल दिया गया है. केवल 10 चीनी मिलों को अभी भी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में ज्यादातर रहे हैं जो कुचल कर रहे हैं. पिछले साल अप्रैल के अंत तक, उत्तर प्रदेश शुगर वसूली के 9.18% के साथ चीनी के 74.8 लाख टन का उत्पादन किया था. कर्नाटक ऐतिहासिक चीनी की रिकवरी के 10.99% से कम चीनी उत्पादन का 41.7 लाख टन होने का है, जो आज तक उच्चतम कभी चीनी, उत्पादन किया गया है.

कमजोर मानसून का असर

दिल्ली। मानसून विभाग ने रिपोर्ट जारी करके मानसून के कमजोर रहने का अंदेशा जताया है. इसके चलते मुख्य प्रभावित होने वाले राज्यों में पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा हैं. कमोडिटी बाजार के लिहाज से कल ग्वार, सोयाबीन, चीनी के भाव महत्वपूर्ण रह सकते हैं. धान, ग्वार, सोयाबीन, चीनी जैसी कमोडिटीज पर इस कमजोर बारिश का सबसे अधिक असर पड़ेगा. कमोडिटी बाजार में ट्रेड करने के लिहाज से ट्रेडर्स को ग्वार, चीनी और सोयाबीन जैसी कमोडिटी पर नजर रखनी चाहिए. इनमें आने वाले दिनों में इनमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है. गौरतलब है कि धान का वायदा फिलहाल भारत के एक्सचेंजों में ट्रेड नहीं होता है. मौसम विभाग के जानकारों के मुताबिक भारत का पश्चिम-उत्तरी हिस्सा (पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गोवा) इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, जबकि दक्षिण भारत में मानसून सामान्य रहेगा और पश्चिमी भारत के कुछ इलाकों में कम बारिश की संभावना है. ध्यान देने वाली बात है कि ग्वार, सरसो, धनिया आदि महत्वपूर्ण कमोडिटी इन्हीं हिस्सों से आती है. आम आदमी के लिहाज से यह बात ध्यान देने वाली है कि आने वाले दिनों में चीनी, सोयाबीन जैसी कमोडिटीज में तेजी देखने को मिल सकती है.

किसान भाईयों अपना क्षेत्र कम पानी वाला अर्थात सूखे का क्षेत्र है इसमें रासायनिक खेती और महंगी होती जाएगी तथा पैदावार घटती जाएगी इसमें पूरी फसल समाप्त होने के खतरे ज्यादा है। रासायनिक खेती में रोगों का खतरा ज्यादा रहता है। मृदा स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है व पर्यावरण प्रदूषण भी एक मुख्य समस्या है रासायनिक खेती से उत्पन्न खाद्यान्नों के प्रयोग से मनुष्य स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैविक खेती इन समस्याओं को हल करने में काफी हद तक सहायक है। जैविक खेती रासायनिक खेती से बहुत सस्ती है जमीन और जीवन दोनों को बचाने के लिए लिए इसे अपनाना जरूरी है 1960 से 1990 तक कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए जिस तेजी से रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल किया गया उसने हमारे जीवन और खेती दोनों को संकट में डाल दिया है उस समय पर्यावरण की अनदेखी की गई जिसकी कीमत हमें आज चुकानी पड़ रही है। 1990 के दशक में भारत सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु एक अभियान शुरू किया जो अब भी जारी है द्वितीय हरित क्रान्ति लाने के लिए जैविक खेती पर ध्यान दिया जा रहा है। और किसानों को इसके लिए तैयार किया जा रहा है। जैविक खेती हर तरह से सुरक्षित और ज्यादा मुनाफा देने वाली है।

हमारे देश में जैविक खेती का इतिहास लगभग 500 साल से भी अधिक पुरानी है। यह सजीव जैविक खेती ही थी जिसने इतने लम्बे समय तक लगातार उन्नत उत्पादन के साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाये रखा। जैविक खेती राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा व पोषणीय सुरक्षा में सहायक है।

जैविक खेती खाद्यान्न फसलों के साथ-साथ बागवानी फसलों में भी उपयोग में ली जा सकती है तथा लागत मूल्य लगभग शून्य के बराबर होता है। फसलों को बढ़ने के लिए और अपज लेने के लिए जिन जिन संसाधनों की आवश्यक होती है वे सभी घर में ही उपलब्ध करना किसी भी हालत में मंडी या बाजार से खरीदकर नहीं लाना। यही जैविक खेती है जैविक खेती का नारा है। गाँव का पैसा गाँव में, गाँव का पैसा शहरों में नहीं। बल्कि शहरों का पैसा गाँव में लाना ही गाँव की जैविक खेती है। फसलों को बढ़ने के लिए जो प्यास मात्रा में मौजूद है ऊपर से कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारी भूमि अन्नपूर्णा है। हमारी फसले भूमि से कितने तत्व लेती है केवल 1.5 से 2 प्रतिशत मृदा से लेती है बाकी 98 से 98.5 प्रतिशत हवा सूरज की रोशनी और पानी से मिलते हैं।

जैविक खेती के उद्देश्य -

- खेती की लागत कम करके अधिक लाभ लेना,
- जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना
- रासायनिक खाद और कीटनाशियों के प्रयोग में कमी लाना
- कम सिंचाई से अधिक उत्पादन लेना

मिट्टी परीक्षण-महत्व एवं लाभ

(1) मिट्टी परीक्षण के द्वारा मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा मालूम हो जाती है। जिससे उर्वरकों की संतुलित मात्रा का उपयोग किया जा सकता है।

(2) उर्वरकों के संतुलित उपयोग से उपज अधिक प्राप्त होती है। जिससे लागत में कमी एवं शुद्ध लाभ में वृद्धि होती है।

(3) कौन सा उर्वरक कितनी मात्रा में डालना है यह ज्ञात हो जाता है।

मिट्टी के नमूने एकत्रित करने का तरीका

(1) प्रत्येक खेत से अलग अलग नमूना लेवें। नमूना फसल का बोनी के पहले इकट्ठा करना चाहिए। जबकि खेत में कोई रासायनिक उर्वरक या गोबर की खाद व कम्पोस्ट खाद इत्यादि डाले न गये हों।

(2) यदि एक ही खेत के अलग अलग भागों में खड़ी फसलों की पैदावार में असमानता हो, मिट्टी का रंग अलग अलग हो, खेत का ढलान ऊंचा नीचा हो या खेत को विभिन्न भागों को विभाजित कीजिये और प्रत्येक का अलग अलग मिला जुला नमूना लीजिये।



लिया जाये तो वही आकार का

(3) एक समान क्षेत्र से मिला जुला नमूना लेने के लिये ज्यादा से ज्यादा 5 एकड़ रकबे से 5 से 10 विभिन्न स्थानों से थोना नमूना एक तसले या टोकरी में एकत्रित कीजिये।

(4) नमूना लेने से पूर्व जमीन में से घांस फूस साफकर दीजिये, अगर नमूना खुरपी या फवड़ा से

(5) खेत सूखा हो व जहाँ फसलें कतारों में बोई हो, वहाँ कतारों के बीच में से नमूना लीजिये।

(6) असामान्य स्थानों जैसे बांध, सिंचाई, नालियों, दलदली जमीन, पेड़ के पास, खाद के गड्ढे और खाद डाले गये स्थानों से नमूना न लें।

(7) संतोषप्रद नमूना लेने के लिये मिट्टी निकालने की नली या वरमा चाहिए। यदि नली या वरमा न हो तो फवड़ा या खुरपी का उपयोग करें।

(8) इकट्ठी की हुई मिट्टी को एक कागज या कपड़े पर अच्छी तरह मिलाकर इसकी चौथाई भाग के चौथाई भाग को लेकर शेष मिट्टी छोड़ दीजिये। उस ली हुई मिट्टी में से आधा कि.ग्रा. मिट्टी निकाल लीजिये कुछ देर छाया में सुखाने के बाद कपड़े की थैली में मिट्टी भर

(9) उर्वरकों कीटनाशकों की तुलना में 75-85 प्रतिशत सस्ते हैं व कम लागत में तैयार किए जा सकते हैं।

(10) स्थानीय उपलब्धता - जैविक कृषि उत्पादों की उपलब्धता ग्राम स्तर पर ही हो जाती है स्थानीय संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग से जैविक खादों आसानी से तैयार की जा सकती है।

-किसानों की बाजार निर्भरता में कमी लाना।

जैविक खादों के गुण:-

(1) कम लागत -जैविक खेती में कम में आने वाले पदार्थ रासायनिक

उत्पाद अधिक स्वास्थ्य वर्धक होते हैं।

(6) विविधकरण - जैविक तकनीक व स्थानीय कृषि तकनीक से समन्वित कृषि का विकास होता है। जैविक खेती जैव विभिन्नता व विविधकरण के संतुलित विकास में सहायक है।

(7) किसान व किसान मित्रवत - कम लागत, स्थानीय निर्माण व उपयोगिता के विभिन्न गुण जैविक खेती को किसानों के लिए मित्रवत बनाते हैं। जैविक खेती से मृदा में जलधारण क्षमता पी.एच.मान व जीवाश्म अनुपात आदि में वृद्धि होती है।

(8) आय में वृद्धि - गाँवकी समृद्धि - जैविक खेती में कम लागत व गुणोत्तर उत्पादन से सकल आय में बढ़ोतरी होती है।

(9) निर्यात में प्रोत्साहन - जैविक खाद्यान्न की पश्चिमी देशों में बहुत माँग है। जैविक कृषि उत्पादों की बिक्री व निर्यात में प्रोत्साहन तो मिलता ही है कृषि उत्पादों पर बाजार में 60-40 प्रतिशत अधिक मूल्य भी मिलता है।

(10) खरपतवार एवं कीट प्रबन्धन - जैविक पदार्थों के लगातार उपयोग से रासायनिक विधि की तुलना में खरपतवार व कीटों के प्रबन्धन में कमी आती है। जिसके परिणाम स्वरूप हानिकारक आयाम जैसे मित्र कीटों की कीटों की कमी, प्रदूषण व खाद्य श्रृंखला में विश प्रकोप आदि से बचा जा सकता है।

(11) भण्डारण क्षमता - जैविक खादों के प्रयोग से उत्पादित कृषि की भण्डारण क्षमता में तुलनात्मक रूप से लगभग 30-40 प्रतिशत अधिक होती है।

निष्कर्ष:-

मृदा स्वास्थ्य में सुधार हेतु पर्यावरण प्रदूषित को रोकने लिए जैविक खेती को अपनाना जरूरी है। कम लागत, अधिक बाजार भाव व अधिक भण्डारण क्षमता इससे मुख्य फायदें हैं किसान व मृदा स्वास्थ्य को सुधारने हेतु जैविक खेती

आज के समय की मुख्य आवश्यकता है।

-राजेश कुमार, योगेन्द्र कुमार मीणा, बजरंग लाल ओला और हरिदयाल चौधरी

-राजेश कुमार शोध छात्र विद्यावाचस्पति, सस्य विज्ञान विभाग, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (राजस्थान)

-योगेन्द्र कुमार मीणा - शोध छात्र विद्यावाचस्पति, सब्जी विज्ञान विभाग, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना,

-बजरंग लाल ओला स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

-हरिदयाल चौधरी-शोध छात्र विद्यावाचस्पति, उद्यान विज्ञान विभाग, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (राजस्थान)

मृदा परीक्षण हेतु मिट्टी के नमूने एकत्रित करने का तरीका

दीजिये।

मिट्टी को एकत्रित करने की विधि

(1) प्रत्येक खेत से अलग-अलग नमूना लेवें।

जब खेत का रकवा फसल की वृद्धि में जमीन के प्रकार से समतल न हो या अलग अलग तरह की फसलें तथा भिन्न भिन्न प्रकार के उर्वरक दिये गये हो तब उसके अनुसार विभाजन करके नमूने एकत्रित करें।

(2) मिला जुला नमूना लीजिये।

प्रत्येक खेत में से मिला जुला नमूना लीजिये। नमूना लेने से पूर्व खेत के ऊपर सतर साफकीजिये। तत्पश्चात् 6 इंच की गहराई तक से 15-20 स्थानों से नमूने एकत्रित कीजिये।

(3) जहाँ फसलें कतारों में बोई हो, वहाँ कतारों के

बीच में से नमूना लीजिये।

असामान्य स्थानों जैसे बांध, सिंचाई, नालियां, दलदली जमीन, पेड़ के पास, खाद के गड्ढे और खाद डाले गये स्थानों से नमूना न लें।

(4) सही औजार का उपयोग करें। उचित नमूने एकत्रित करने के लिये सही औजार का उपयोग करें।

(5) सही आकार के गड्ढे से नमूना एकत्रित करें।

15 से 20 से.मी. के त्रिकोण गड्ढे से नमूना निकाले।

नमूना लेते समय ध्यान रखने योग्य बातें

1. नमूना सूखे खेत से लें। 2. ढलान के अंत से या गड्ढे से नमूना न लें। 3. मेढों के पास से तथा वृक्षों की जड़ों के पास से नमूना न लें। 4. गोबर की खाद एवं उर्वरक या सिंचाई की नालियों के पास से नमूना न लें। 5. सूचना पत्रक सावधानी से भरें 6. सूक्ष्म तत्वों के परीक्षण हेतु नमूना लेते समय स्टैनलेस स्टील या लकड़ी से बने औजारों का ही उपयोग करें।

लेखन एवं संकलन-

श्रीमती गीता सिंह विषय वस्तु विशेषज्ञ (कृषि विस्तार),

कृषि विज्ञान केंद्र, डिण्डौरी

श्रीचन्द्रशेखर सिंह (परियोजना अधिकारी) जिलापंचायत डिण्डौरी (म. प्र.)

भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हमारे देश में प्राचीनतम समय से कृषि की जा रही है। हमारे पूर्वजों के पास कृषि का महत्वपूर्ण ज्ञान था, लेकिन समयानुसार हम अपनी प्राचीन कृषि को भूलकर नई पद्धतियों को अपनाने में लग गये। इसके परिणाम से हमारी भूमि दिनों दिन खराब होती जा रही है। आज हमें आवश्यकता है कि पूर्वजों के द्वारा दिये गये कृषि ज्ञान को अपनाकर बेकार होती जा रही कृषि योग्य भूमि को बचाया जा सके।

भारत में खेती हजारों वर्षों से की जा रही है। जब कि यूरोप का अस्तित्व ही नहीं था। हमारे ऋषियों ने अपने विवेक, ज्ञान और परिणाम से कृषि समस्याओं का हल जैविक विधि से निकाला था, चूँकि ये ऋषि आश्रमों में प्रकृति के बीच, पशु, पक्षियों, पौधों, वनों, वृक्षों, झरनों आदि से घिरे रहते थे उनको इन सबके बारे में अति सूक्ष्म ज्ञान ही नहीं वरन् उनसे प्रेम भी था और उनका महत्व भी जानते थे ऋषि मनु ने कहा था कि जो मनुष्य बेकार बीज को सही बताकर बेचता है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिये। आज हम पश्चिमी कृषि से प्रभावित होकर पूर्वजों के ज्ञान को भूला चुके हैं। आज जब पश्चिमी देशों ने कार्बनिक खेती की बात की तो सबका ध्यान गोबर की खाद की ओर गया। जबकि हमारे महर्षि अर्थ शास्त्री कौटिल्य ने ईसा से 400 वर्ष पूर्व ही खेत में गोबर की खाद काम में लेने पर जोर दिया था। जिस तरह एक शिशु के लिये दुग्ध महत्वपूर्ण आहार है उसी तरह पौधों के लिये सही प्रकार से बनी गोबर की खाद सम्पूर्ण आहार है।

हरित क्रांति के पश्चात् दो दशकों में कृषि उत्पादकता में कोई महत्वपूर्ण खोज नहीं हुई जिससे बढ़ती हुई आबादी के लिये खाद्य आपूर्ति व आज की योजनाओं जैसे 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन' हेतु खाद्य आपूर्ति की जा सके। इस संदर्भ में हमारी कृषि विरासत को जानना आवश्यक है। भारतीय कृषि जैमिनी पाराशर एवं कश्यप ने यह रास्ता दिखलाया जिससे बेहतर व टिकाऊ कृषि, वृक्ष, पर्यावरण, जंगल, जल, जमीन व पशुओं को सम्मान देते हुए इनमें संतुलन रखा जा सके। उन्होंने कहा कि धनवान, जवाहरात, गहने, अच्छी पौशाकें हैं। उन्हें भी किसानों से ऐसी याचना करनी चाहिये जैसे भक्त भगवान से करता है व 'अन्नदाता' नाम से सम्मान करना चाहिये। यह समय हमारी कृषि विरासत का अध्ययन करने का है हमारे देश के प्राचीन एवं मध्य युगीय काल के साहित्य में पर्यावरण संसाधनों और आध्यात्मिकता का समावेश है। दन साहित्यों के गंभीरतापूर्वक अध्ययन तथा वर्णित ज्ञान को पुनः अंगीकार करने की आवश्यकता है जिससे समाज का पुनःनिर्माण किया जा सके व कृषकों का मनोबल बढ़ाया जा सके।

हमारे पुराने साहित्यों में लिखा है -

-खेत जोतने के लिये माह का 2,3,5,7,10,11 व 13 वां दिन अच्छा माना जाता है। 4 वें दिन कीटों का नुकसान का डर रहता है। शनिवार को बुवाई से कीड़ों व टिड्डों का डर रहता है।

-खाद बनाने के लिये गोबर को सुखाकर पाऊंडर बनाकर सड़ने के लिये खड्डे में डालना चाहिये, जिससे गोबर जल्दी सड़ता है और गोबर में उपस्थित सभी खरपतवार के बीज भी नष्ट हो जाते हैं।

-यदि खेत की जुताई गहरी की जावे व मिट्टी को इतना सुखने देवें कि वजन का एक चौथाई रह जावे तो खाद देना भी आवश्यक नहीं होता आदि।

कनुपजल:

वैसे तो भारत वर्ष में खेती का प्रयोग हजारों वर्षों से चल रहा है। कनुपजल एक द्रवीय जैविक खाद है जिसका उल्लेख सुरपाल के वृक्षायुर्वेद में मिलता है। पशुओं और पौधों के अवशेषों को विभिन्न मात्राओं

प्राचीन कृषि का इतिहास एवं पारम्परिक संरक्षण के तरीके



के अनुसार मिश्रण बनाकर कुछ समय खमीर उठाने की प्रक्रिया की जाती है। उपवनविनोद एवंविश्ववल्लभ में इसका वर्णन मिलता है। उसका उपयोग कई फसलों में किया गया है जिनके अच्छे परिणाम भी मिले हैं। कनुपजल पौधों को न केवल पोषण देता है बल्कि व्याधियों से भी बचाता है।

प्राचीन भारत से अपनाए जा रहे कृषि उत्पाद संरक्षण के तरीके आज भी प्रचलित हैं यह सभी पर्यावरण रक्षित होने के साथ-साथ स्वास्थ्य परक भी है।

अ. नमक द्वारा: साधारण खाने के काम में आने वाले नमक को खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भण्डारण हेतु काम में लिया जाता है। इसके लिये 200 ग्राम प्रति किलो खाद्य पदार्थ की दर से मिलाया जाता है। जिससे खाद्य पदार्थ खराब होने से बच जाता है। इसके द्वारा लाल दाल, मसूर दाल, लाल मिर्च पाऊंडर, इमली आदि को संरक्षित किया जाता है।

ब. नीम या तुम्बाई की पत्तियों द्वारा: रागी अनाज को आज भी नीम की या तुम्बाई की सूखी पत्तियों द्वारा संरक्षित किया जाता है। तीखी गंध होने की वजह से इन पत्तियों से कीड़े-मकोड़े दूर रहते हैं और अनाज सुरक्षित रहता है।

स. निम्बोली के घोल द्वारा: जिन भी बोरियों में अनाज को भरकर सुरक्षित रखना है उन्हें पहले निम्बोली के घोल द्वारा धो लिया जाता है। इसके लिये निम्बोलियों को पीसकर उसका रस निकाल लें या इसका 10 किलोग्राम पाऊंडर 100 लीटर पानी में 24 घण्टे भिगोकर रखें फिर बोरियों में अनाज को भरकर रखने से लम्बे समय तक सुरक्षित रहता है।

द. नीम तेल द्वारा: अनाज व दालों में 20 मिलीलीटर नीम तेल को प्रति किलो अनाज की दर से मिलाने से अनाज एक वर्ष तक खराब नहीं होता है। नीम तेल अनाज को कीड़ों के प्रकोप से बचाता है।

य. अरण्डी के तेल द्वारा: अनाज व दालों में अरण्डी के तेल को मिलाकर रखने से भी अनाज को सुरक्षित रखा जा सकता है। काम में लेने से पहले चावल व दालों को गर्म पानी से 2-3 बार धोकर ही काम में लेना चाहिये।

र. कपूर द्वारा: अनाज व दालों को कीड़ों से बचाने के लिये यदि एक ग्राम कपूर का टुकड़ा प्रति 5 किलोग्राम अनाज की दर से डिब्बों में रख दिया जाये तो अनाज कम से कम तीन महिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ज्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिये इस क्रिया का दोबारा व तिबारा भी अपनाया जा सकता है। दुबारा उपयोग से पहले एक बार अनाज को धूप में सुखा लेना चाहिये ताकि उसे पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके।

ल. नींबू द्वारा: दालों को सुरक्षित रखने के लिये नींबू को सुखाकर उसका पाऊंडर भण्डारण में काम में लेना चाहिये। 10 ग्राम नींबू का पाऊंडर प्रति एक किलो दाल के हिसाब से प्रयोग में लिया जाता है। नींबू की अम्लीय प्रवृत्ति होने की वजह से इसके सम्पर्क में कीड़े-मकोड़े एवं फंफूँ नहीं आती है। यह कीड़े-मकोड़े के शरीर पर जलन पैदा कर देता है अतः वे इससे दूर रहते हैं। इसके प्रयोग से अनाज को एक वर्ष तक सुरक्षित रखा जा सकता है।

व. राख द्वारा: ज्वार, चावल, जौ, बाजरा आदि के दानों में राख मिलाकर रखने से वह लम्बे समय तक सुरक्षित रहते हैं। साथ ही राख लहसुन को सुरक्षित रखने के भी काम में आती है।

ह. भण्डारों द्वारा: गांवों में कई तरह के भण्डारों द्वारा अनाज को सुरक्षित रखा जाता है। यदि मिट्टी से बने भण्डारों को भेड़ की मींगणियों को मिट्टी में मिलाकर लीपने से भी भण्डार गृह एवं अनाज को सुरक्षा मिलती है।

अतः आज की महती आवश्यकता है कि हजारों वर्षों से चली आ रही व कृषि अनुसंधानों के आधार पर किये गये तथ्यों को फिर से अंगीकार कर खाद्य आपूर्ति, टिकाऊ खेती व खाद्य सुरक्षा की ओर से कदम बढ़ावें।

- डॉ. लतिका व्यास व डॉ. पीयूष जानी

IMPORTER - STOCKIEST - BULK SUPPLIER CHEMICALS - SOLVENTS - AGRO - FERTILISER - MICRO NUTRIENTS

AMINO ACID
AMMONIUM CHLORIDE
AMMONIUM SULPHATE
BENTONITE
BORON
BRONOPOL
CALCIUM NITRATE
COPPER SULPHATE
CYCLOHEXANONE
DI AMMONIUM PHOSPHATE
DI POTASSIUM PHOSPHATE
EDTA
FERROUS SULPHATE
FOLIC ACID

GYPHOSUM (POWDER / GRANULAR)
HUMIC ACID
ISO PROPYL ALCOHOL
MAGNESIUM SULPHATE
MAGNESIUM NITRATE
MANGANESE SULPHATE
MONO AMMONIUM PHOSPHATE
MONO POTASSIUM PHOSPHATE
NITROBENZENE
PHOSPHORIC ACID
POTASSIUM CHLORIDE
POTASSIUM NITRATE
POTASSIUM SULPHATE

SINGLE SUPER PHOSPHATE
SULPHUR
TOLUENE
UREA
VITAMINS
ZINC SULPHATE
(MONO / HEPTAHYDRATE)

NPK (ALL GRADE
WATER SOLUBLE FERTILIZERS)

19-19-19	20-20-20	20-10-10
13-00-45	00-52-34	17-17-17
00-00-50	15-15-15	12-32-06
12-61-00	18-18-10	13-40-13
	20-20-0	

A. S. JOSHI & COMPANY (SINCE 1971)

Add : 813, Topiwala Center, Off. S.V. Road, Goregaon (West),
Mumbai - 400062 off : +91 22 65093952 / 53 Mob : +91 9324239400
Email : Sales.Joshibchem@gmail.com • Web : www.JoshiChem.com

अमानीशाह नाले में प्रदूषित पानी से उगायी जा रही हैं सब्जियां



जयपुर, जिला कलक्टर श्री कृष्ण कुणाल ने शहर से गुजर रहे अमानीशाह नाले के 13 चिन्हित सम्पूर्ण क्षेत्रों में प्रदूषित पानी से उगायी जा रही सब्जियां एवं अन्य पैदावार को 9 से 12 मई तक अभियान के रूप में हटाये जाने के लिए जयपुर नगर निगम एवं जयपुर विकास प्राधिकरण एवं आवासन मण्डल के अधिकारियों को मय आवश्यक संसाधन के साथ उपस्थित होकर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाही के दौरान पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी मय जाते के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए गये हैं।

श्री कुणाल यहां जिला कलक्टर सभाकक्ष में अमानीशाह नाले में प्रदूषित पानी से उगायी जा रही सब्जियों एवं अन्य पैदावार

को हटाये जाने के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने इस कार्यवाही के दौरान जेडीए को प्रत्येक स्थल पर वीडियोग्राफर्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ये वीडियोग्राफर्स उगायी गयी सब्जियों एवं अन्य फसलों को हटाने की सम्पूर्ण कार्यवाही की रिकार्डिंग करेंगे। उन्होंने कहा कि आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, पुलिस एवं जलदाय विभाग सहित अन्य संबंधित विभाग स्तर पर एक नोडल आफिसर की नियुक्ति की जाये जिला कलक्टर ने जयपुर नगर निगम एवं जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को नाला क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों में अभियान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में

अभियान से पूर्व क्षेत्रीय निवासियों को जानकारी हो इसकी व्यवस्था प्रेस एवं ध्वनी प्रसारण यंत्र एवं अन्य सुलभ संसाधनों से सुनिश्चित करायी जाये ताकि संबंधित लोगों द्वारा स्वयं ही सब्जियां, पैदावार हटायी जाती है तो यह व्यवस्था और अधिक सुविधाजनक रहेगी।

उन्होंने इस कार्यवाही के दौरान फोक लेण्ड मशीन का उपयोग लिये जाने के निर्देश देते हुए कहा कि ट्रैक्टरों की संख्या का आंकलन करते हुए पर्याप्त ट्रैक्टरों की व्यवस्था की जाये। नाला क्षेत्र में उगायी जा रही समस्त पैदावार को हटाया जाये। यदि नाले के बगल या आस पास से कोई पाइपलाइन गंदे पानी को ले जाने हेतु जा रही हो तो मौके पर ही उसे तुड़वाया/हटाया या बद करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

जिला कलक्टर ने कहा कि नाला क्षेत्र में पैदावार हटाने की कार्यवाही के तत्काल बाद उसी दिवस जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से साईन बोर्ड लगवाये जाये कि नाला क्षेत्र में सब्जियां, फसल, पैदावार पूर्णतया प्रतिबंधित है। अभियान के अन्तर्गत कार्यवाही के दौरान संबंधित थानाधिकारी/जयपुर नगर निगम/जयपुर विकास प्राधिकरण के सतर्कता शाखा के अधिकारी/संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट उपस्थित रहेंगे।

कानोता बांध में दूषित पानी को रोकने के संबंध में कमेटी गठित।

चार हजार की आबादी वाले कस्बों में श्री फेस बिजली मिलेगी

जयपुर। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक श्री बी. राणावत ने कहा कि उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता पूर्ण बिजली उपलब्ध कराने के लिए निगम कृत संकल्पित हैं। इसके लिए ऐसे चार हजार की आबादी वाले कस्बों में शहरी क्षेत्र की तरह ही 24 घंटे श्री फेस बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।

अधीक्षण अभियंता एवं सहायक अभियंता कार्यालय खोलने पर होगा विचार -

चौपाल में प्रबंध निदेशक ने बताया कि कुचामनसिटी में विद्युत भार को देखते हुए यहां अधीक्षण अभियंता एवं एक सहायक अभियंता का कार्यालय खोलने पर भी प्रस्ताव तैयार कर विचार किया जाएगा।

जीएसएस बनेंगे इसी माह: प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि विद्युत आपूर्ति सुचारू बनाये रखने के लिए कुचामनसिटी के लिए दो जीएसएस उग्रपुरा एवं खारडा का निर्माण करवाया जा रहा है

सिंगल फेस पर लोड बढ़ाया जाएगा - प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि बताया कि सिंगल फेस लाईन पर अधिक कनेक्शन होने से बिजली आपूर्ति में व्यवधान होता है इसके लिए पर्याप्त ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवा कर लोड बढ़ाया जाएगा।

टोल फ्री नम्बर पर होगा समस्या का समाधान

प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि उपभोक्ताओं

की सुविधा के लिए निगम ने टोल फ्री नम्बर दिए गए हैं ताकि उपभोक्ता अपनी बिजली संबंधी समस्या को इस टोल फ्री नम्बर पर दर्ज करवा सकते हैं।

शहर में बिजली एक साथ बंद नहीं हो: प्रबन्ध निदेशक ने चौपाल के दौरान किसी भी आपूर्ति संबंधी समस्या पर पूरे शहर की बिजली को बंद करने की समस्या सामने आने को गंभीरता से लेते हुए सहायक अभियंता को निर्देश दिए कि वे तत्काल आइसोलेटर लगाने के प्रस्ताव तैयार करें

बीपीएल कनेक्शन मिलेंगे: प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि बीपीएल कनेक्शन सभी को उपलब्ध कराए जाएंगे इसके लिए टेण्डर आमंत्रित कर दिए गए हैं तथा जून माह में खुलने लग जाएंगे ताकि सभी बीपीएल को कनेक्शन मिल सकेंगे। उन्होंने बताया कि गैर आबादी क्षेत्र में घरेलू कनेक्शन के लिए डीपी एवं लाईन लगाने का व्यय उपभोक्ता द्वारा दिए जाने पर कनेक्शन दे दिया जाएगा।

फोटो बिलिंग होगी: प्रबन्ध निदेशक ने सहायक अभियंता को निर्देश दिए कि वे मीटर रीडर के माध्यम से मीटर की फोटो आवश्यक रूप से कराए ताकि फोटो बिलिंग जारी हो सके। जिससे उपभोक्ताओं को सही मिल सकें।

लाईन शिफ्टिंग पर 50 प्रतिशत राशि देनी होगी: प्रबन्ध निदेशक को चौपाल में समस्या दी गई कि कई मकानों के ऊपर से विद्युत लाईन जा रही हैं।

15 दिन में देगी रिपोर्ट

जयपुर। जिला कलक्टर श्री कृष्ण कुणाल ने कानोता बांध में दूषित पानी की समस्या के निराकरण हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण के डायरेक्टर इंजीनियर की अध्यक्षता में 15 सदस्यी समिति का गठन किया है जिसे 15 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। इस समिति में उपखण्ड अधिकारी एवं विकास अधिकारी बस्सी एवं जमवारामगढ़, नगर निगम के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सहित जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी, जलसंसाधन विभाग के अधिकारी इत्यादी को शामिल किया गया है। जिला कलक्टर कलेक्टर के सभागार में कानोता बांध में दूषित पानी के निराकरण के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह समिति कानोता बांध में आने वाले दूषित पानी की रोकथाम के लिए किये गये उपायों तथा भविष्य में इस बांध को दूषित पानी से पूर्णतः मुक्त करने के लिए और अधिक आवश्यक उपायों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट 15 दिन में प्रस्तुत करेगी। उन्होंने जयपुर विकास प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव को निर्देशित किया कि इस बांध में जल महल के पीछे की तरफ से आने वाले दूषित पानी को रोकने के लिए जेडीए द्वारा इस क्षेत्र में बनाये जा रहे 50 एमएलडी के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को पूर्ण क्षमता के साथ तैयार किया जा कर दूषित पानी को बांध में जाने से तुरन्त रोका जाये। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे शहर में कचरा डालने के लिए अलग अलग स्थानों को चिन्हित करें तथा इसके लिए भूमि आवंटन हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन को आवेदन करें।

खाद्य सुरक्षा योजना में गेहूं का आवंटन

जयपुर। राज्य में खाद्य सुरक्षा योजनांतर्गत पात्र लाभार्थियों एवं अन्त्योदय परिवारों के लिए माह मई व जून 2014 हेतु शहरी क्षेत्र के लिए 42 हजार 263 मै. टन एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक लाख 88 हजार 870 मै. टन कुल 2 लाख 31 हजार 133 मै. टन गेहूं का आवंटन किया गया है।

सत्रह जिलों के 10 हजार 225 गांव अभावग्रस्त घोषित

जयपुर। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर राज्य के 17 जिलों के 10 हजार 225 गांवों को अकाल से प्रभावित होने के कारण अभावग्रस्त घोषित किया है। इन गांवों में 31 जुलाई, 2014 तक भू-राजस्व वसूली स्थगित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। आदेशानुसार अजमेर जिले के 104 गांवों, अलवर के दो, बांसवाड़ा के एक हजार 501, बाड़मेर के एक हजार 507, बारां के 482, बीकानेर के 339, चूरू के 16, डूंगरपुर के 986, जोधपुर के 868, सिरोही के 272 एवं प्रतापगढ़ के एक हजार आठ गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। इसी प्रकार कोटा जिले के 281 गांवों को, जैसलमेर के 744, झालावाड़ के एक हजार 72, नागौर के 103, पाली के 934 तथा बूंदी जिले के छह गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। भू-अभिलेख में दर्ज ऐसी भूमि जो बारानी, तालाबी अथवा सैलाबी है किन्तु उन भूमि पर कुओं या अन्य स्रोतों से सिंचाई होती है, पर भू-राजस्व वसूलने में प्रभावी नहीं होंगे। भू-अभिलेख में दर्ज देहरी, सेवज, खड़ीन, सैलाबी, तालाबी पेटा, क'छार एवं खातली भूमि को छोड़कर समस्त बारानी भूमि को भू-राजस्व के संदाय से मुक्त होगी।



ग्रामीण क्षेत्रों में लगेगी 10 विद्युत चौपालें

जयपुर। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने के लिये अजमेर जिला वृत्त में 10 स्थानों पर विद्युत चौपालों का आयोजन किया जाएगा।

निगम के अधीक्षण अभियंता (अ.जि.वृ.) श्री डी. एन. जांगिड ने बताया कि यह विद्युत चौपालें ग्रामीण कनिष्ठ अभियंता मुख्यालय (33/11 के.वी. सब स्टेशन) पर प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक आयोजित की जायेगी। ये चौपालें गोहाना, अमरसिंह का बाडिया, काबरा, पाटन, करकेड़ी, श्रीनगर, सरवाड़, केकड़ी, जालिया-द्वितीय एवं सावर के सहायक अभियंता क्षेत्र में लगेगी। समस्त विद्युत चौपालों में संबंधित प्रधान, सरपंच एवं जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। चौपाल में प्राप्त शिकायतों का पंजीयन कर समयबद्धता से निस्तारण भी किया जाएगा।

मंथन

ग्रामीण क्षेत्रों में घटता जल स्तर



जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल स्तर की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। तीन विकास खंड और छह न्याय पंचायतों के 165 गांवों में भूजल स्तर की सरकारी रिपोर्ट खतरे का सिग्नल देती नजर आती है। 39 गांवों में वर्तमान में 10 से 18 मीटर की गहराई पर पेयजल उपलब्ध है। ज्यादातर गांवों में पानी स्वादहीन हो रहा है। विकास खंड रजापुर के भोवापुर गांव में पेयजल स्तर सबसे नीचे पहुंच गया है।

भीषण गर्मी में प्रतिवर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेयजल संकट के लिए हाहाकार की स्थिति रहती है। शहरों में दोहन की वजह से भूजल स्तर में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। गांवों में भी हालत अच्छी नहीं देखी जा रही। भूजल स्तर में कमी आने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ रही है। इसके अलावा पानी का स्वाद बदल रहा है। कुछ गांवों का पानी पीने योग्य तक नहीं है। सूत्रों के मुताबिक तीन विकासखंड और छह न्याय पंचायतों के 165 गांवों में भूजल स्तर से जुड़ी रिपोर्ट कुछ समय पहले जिला प्रशासन को सौंपी गई थी। यह रिपोर्ट कम परेशान करने वाली नहीं है।

सरकारी रिपोर्ट में विकास खंड रजापुर के 35, विकास खंड मुरादनगर के 45, विकास खंड लोनी के 34, न्याय पंचायत भोजपुर के 7, न्याय पंचायत भदौला के 10, न्याय पंचायत तलहैटा के 8, न्याय पंचायत कादराबाद के 8, न्याय पंचायत बेगमाबाद और अतरौली के 9-9 गांवों में भूजल स्तर की मौजूदा स्थिति का जिक्र किया गया है 39 गांवों में इस समय कम से कम 10 मीटर और अधिक से अधिक 18 मीटर पर पेयजल उपलब्ध है। रिपोर्ट के मुताबिक विकास खंड रजापुर के ग्राम भोवापुर में 18 मीटर पर, शाहपुर निज मोरटा, मथुरापुर, बहादुरपुर में 15 मीटर पर और अटौर, मोरटा, शमशेर में 12 मीटर व ग्राम काजमपुर में 11 मीटर से कम पर पेयजल उपलब्ध नहीं है।

पिछले कुछ वर्षों में इन सभी गांवों में भूजल स्तर में निरंतर गिरावट आने के साथ पानी का स्वाद खराब हो रहा है। इसका मुख्य कारण अवैध तरीके से दोहन और फ्रैक्चरिंगों का दूषित पानी बगैर ट्रीट किए जमीन में डाला जाना है। फ्रैक्चरिंगों के खिलाफ सरकारी स्तर पर प्रभावी कार्यवाही का अभाव है। गांवों में तालाब और पोखरों पर अवैध कब्जे हो चुके हैं। ऐसे में बरसाती पानी भी प्रतिवर्ष नालों में बहकर बर्बाद हो जाता है। आवश्यकता है जागरूकता की, सरकारी सही योजनाओं की व उनका सही क्रियान्वत हो सके, इस के लिये मिल कर एक ईमानदार प्रयास करने की

ऋतु कपिल
(कार्यकारी संपादक)

(पाक्षिक राशि फल)

01-05-2014 से

15-05-2014

ज्योतिषाचार्य - पं. जयदत्त व्यास- जयपुर



AJS	अनिश्चितताए कार्य अवरोध एविलम्ब से सफलता के योग!
BKT	स्वजनो से मिल कर चलने से लाभए शारीरिक मानसिक ए दुर्बलता रहे!
CLU	अनिश्चितता का वातावरण रहे ए अंत में लाभपूर्ण योग !
DMV	धन लाभ काम एमेहनत अधिक किसी के सहयोग से कार्य करने से लाभ!
NEW	आकस्मिक रूप से धन हानि ए सावधानी रखें
FOX	परिवारिक रूप से लाभ ए नए व्यक्ति से संपर्क जिससे आगे चल कर लाभ की संभावना
GPY	मानसिक चिंतन अधिकए लाभ हानि साथ साथ !
HQZ	समय का उपयोग ठीक तरह से करने से लाभ विरोधी प्रबल !
IR	अधिनस्थ तथाए अधिकारियों से परेशानियां ण्डहेगणपूर्ण समय !

क्या आप जानते हैं ?

पानीए साफ-सफाई और स्वास्थ्यप्रद स्थितियों के बारे में कुछ तथ्य

1. अगर स्वास्थ्यप्रद स्थितियां या बेहतर स्वस्थ माहौल की बात की जाए तो इसमें निजी साफसफाई से लेकर आसपास का साफसुथरा माहौल भी शामिल होता है। यूं भी पानी से जुड़ी बीमारियों या प्रदूषित पानीए खराब स्वास्थ्य और गरीबी का एक खास दायरा गंदे पानी और साफसफाई की खराब स्थितियों की वजह से सामने आता है।
2. साफसफाई का ध्यान न रखने से पानी प्रदूषित होता है। प्रदूषित पानी यानी जिसमें गंदगी की वजह से सूक्ष्म जीव पैदा होने लगते हैं।
3. दुनिया की 26 अरब से ज्यादा की आबादी में से 40 प्रतिशत बुनियादी सफाई सुविधाओं से महरूम है।
4. दुनिया में एक अरब से भी ज्यादा लोग प्रदूषित पानी का इस्तेमाल पीने के लिए करते हैं।
5. बीमारियों और खराब स्वास्थ्य का सीधा संबंध गंदे पानीए सफाई का अभाव और अस्वस्थकर स्थितियों से है। गंदे पानी और गंदगी से डायरियाए टाइफाइडए पाराटाइफाइडए बुखारए हेपेटाइटिस एए हेपेटाइटिस ई और एफए फ्लुरोसिसए आर्सेनिक जनित बीमारी जैसी बीमारियां होती हैं। कुछ दूसरी बीमारियां हैंरू. लेजिनोलिसिसए मेथमोग्लोबीनेमियाए सिन्टोसोमिपिसिसए

- आंत का संक्रमणए डेंगूए मलेरियाए जापानी इंसेफलाइटिस। वेस्टनील वायरस संक्रमणए येलो फीवर और इम्पेटिगो यानी त्वचा से संबंधित बीमारी भी हो सकती है।
5. दुनिया भर में डायरिया से 1ए085ए000 से लेकर 2ए187ए000 मौतें हो जाती हैं। यह मौतें गंदे पानीए खराब सफाई व्यवस्था और दूषित पानी के कारण हो जाती हैं। डायरिया से मरने वाले 90 फीसदी पांच साल से कम के बच्चे होते हैं।
6. साफऔर गैर हानिकारक पानी की आपूर्तिए बेहतर सफाई और स्वस्थ माहौल डायरिया को 20 प्रतिशत तक घटा सकती है। बेहतर स्थिति से डायरिया से होने वाली 50 प्रतिशत मौतें कम हो सकती हैं।
7. शौच.गृह के इस्तेमाल या बच्चों का मल.मूत्र साफकरने के बाद हाथ धोने और भोजन से पहले हाथों की अच्छी तरह सफाई डायरिया को 33 प्रतिशत कम कर देती है।
8. सफाई का अंतरराष्ट्रीय लक्ष्य पूरा करने के लिए हर साल 14 करोड़ लोगों को बेहतर सफाई व्यवस्था मुहैया करानी होगी। 1990 और 2002 तक सिर्फ साढ़े आठ करोड़ लोगों को ही बेहतर सफाई व्यवस्था मुहैया थी। सरकारों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने यह एक बड़ी चुनौती है।

सूचना

पाक्षिक समाचार पत्र सृष्टि एग्रो में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों व लेखों में समाविष्ट सभी बातों की जाँच-परखकर पाना संभव नहीं है। विज्ञापनों में अपने उत्पादनों अथवा अपनी सेवाओं के बारे में विज्ञापनदाता जो दावे करते हैं, सृष्टि एग्रो समाचारपत्र उसकी कोई गारंटी नहीं लेता। विज्ञापनों में किए गए दावों की पूर्ति यदि विज्ञापनदाता द्वारा नहीं होती है तो उसके लिए पाक्षिक सृष्टि एग्रो समाचारपत्र समूह के मुद्रा, संपादक, प्रकाशक व मालिक किसी भी रूप में जवाबदेह नहीं होंगे, कृपया इसे ध्यान में रखें। अतः हम पाठकों से अनुरोध करते हैं कि विज्ञापन में उल्लिखित बातों के संदर्भ में कोई भी करार करने के पूर्व उसके बारे में आवश्यक छानबीन कर लें।

S.S. AGRO (INDIA) MUMBAI

(DIRECT IMPORT FOR YOUR FERTILIZER/CHEMICALS)

□ ZINK EDTA/COPPER

EDTA/FE EDTA

□ 100% WATER SOLUBLE

FERTILIZER (NPK)

□ HUMIC ACID

□ SEAWEED EXTRACT

□ AMINO ACID

□ POTASSIUM HUMATE

□ FULVIC ACID

□ EDDHA

□ NATCA

□ BRASSINOLIDE

□ DAP

□ SODA ASH

□ SODIUM SULPHIDE

□ AMONIUM CLORIDE

□ SODIUM BICARBONATE

□ CALCIUM CARBIDE

□ PHOSPHORIC ACID

□ TRI SODIUM

PHOSPHATE

□ CITRIC ACID

□ STPP

ALL KIND OF INORGANIC/

Organic Chemicals

CONTACT NO.-022-6710-3722

EMAIL:aarti@hindchem.com

सरसों वैज्ञानिक डॉ. अरविंद कुमार केंद्रीय कृषि विद्यालय, झांसी के कुलपति नियुक्त

भरतपुर। देश के प्रतिष्ठित सरसों वैज्ञानिक डॉ. अरविंद कुमार को राष्ट्रपति द्वारा नवस्थापित रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी का प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया है।

सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर के पूर्व निदेशक एवं वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में उपमहानिदेशक (कृषि शिक्षा) के पद पर कार्यरत डॉ. अरविंद कुमार की कुलपति के पद पर नियुक्ति से देश में राई-सरसों के अनुसंधान में कार्यरत वैज्ञानिकों ने अपार हर्ष व्यक्त किया है।

डॉ. अरविंद कुमार ने वर्ष 2002 से 2009 तक सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर के निदेशक पद पर रहते हुए राई-सरसों अनुसंधान को नई दिशा दी एवं अधिक पैदावार की प्रजातियां एवं उन्नत तकनीकों के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होंने उपमहानिदेशक (कृषि शिक्षा) के



पद पर रहते हुए भारत में कृषि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने एवं विश्व स्तरीय बनाने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता कार्यक्रमों का आयोजन किया एवं देश के 70 कृषि विश्वविद्यालयों के लिए कृषि शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रम तथा उच्च कृषि शिक्षा के लिए पहली बार समान नीति विकसित की।

उन्होंने दुनिया के दो दर्जन देशों की यात्राएं करके वहां अपने शोध पत्र प्रस्तुत किये तथा राई-सरसों अनुसंधान एवं कृषि शिक्षा का अध्ययन करके देश में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉ. कुमार ने कई अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं का प्रतिनिधित्व तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों का आयोजन किया। उन्होंने 150 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध पत्र एवं 8 किताबों का प्रकाशन किया है। इसके अलावा कई वैज्ञानिक एवं प्रशासनिक दस्तावेजों का भी प्रकाशन किया। डॉ. कुमार करीब 27 साल तक पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में भी विभिन्न पदों पर रहे हैं।

निदेशालय के निदेशक डॉ. धीरज सिंह ने कहा कि सरसों अनुसंधान निदेशालय के विकास में डॉ. कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

नैप से कृषि क्षेत्र को मिलेंगी नई तकनीके

दिल्ली। नैशनल एग्रिकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट का गठन कृषि क्षेत्र में नये संशोधन के लिए किया गया। इसके द्वारा विकसित कृषि संबंधी करीब तीस नई तकनीकों को जल्द ही कृषि क्षेत्र में लाया जाएगा। इन नई तकनीकों के लिये मई माह के 18 और 19 तारीख को एक कृषि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।

नैप भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक इकाई है। नैप का गठन वर्ल्ड बैंक की मदद से कृषि क्षेत्र में नई रिसर्च के लिए किया गया था। इस प्रोजेक्ट पर 25 करोड़ डॉलर खर्च किए गए हैं। इसमें से विश्व बैंक द्वारा 20 करोड़ डॉलर दिए गए शेष राशि भारत सरकार ने दी। नैप ने अपने 7 साल के कार्यकाल में कई नई तकनीकों को विकसित किया है। नैप द्वारा विकसित करीब 280-300 में से करीब 80 तकनीकों का लाभ कृषि क्षेत्र में लिया जा रहा है। अब जल्द ही नई तकनीकों को किसानों और उद्यमियों के लिए लाया जा रहा है।



प्री-खरीफ फसल के लिए दिया जाएगा किसानों को पानी

राजकोट। राजकोट सिंचाई विभाग ने 25 डेमें से जिले के गांवों को पानी देने का अहम फैसला लिया है। खरीफ की फसल के लिए सिंचाई विभाग ने 25 डेमें के अलावा 79 जलाशयों में से भी गांवों को पानी देने का निर्णय लेकर किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। वर्तमान में राजकोट, जामनगर और जूनागढ़ जिले के 16 डेमें से किसानों को पानी सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद पानी की कमी बनी हुई है। इसीलिए अब अन्य डेमें से भी पानी लेने का निर्णय लिया गया है। इस बारे में सिंचाई विभाग के नायब कार्यपालक अशोक मशरू ने बताया कि गत वर्ष अच्छी बारिश होने के कारण सभी डेमें में पीने के अलावा सिंचाई के लिए भी पानी का जत्था सरप्लस है। गर्मी का मौसम होने के चलते गांवों से और पानी की मांग उठ रही है। इसीलिए यह फैसला लिया जा रहा है।

शिकारियों से ग्रामीणों ने छुड़ाए जंगली पक्षी



होडल. भिड़की के ग्रामीणों ने रविवार सुबह गांव के निकट जंगल से शिकारियों के कब्जे से दर्जन भर से ज्यादा पक्षी छुड़ाए। ग्रामीणों को एकत्र होता देख शिकारी जंगल से फरार हो गए। शिकारियों ने दो पक्षियों को पत्थर मारकर घायल भी कर दिया था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना हसनपुर पुलिस व वन विभाग के अधिकारियों को दी। पुलिस व विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर इन पक्षियों को कब्जे में ले लिया। भिड़की के ग्रामीणों ने रविवार सुबह दो बाइकों पर चार-पांच लोगों को जंगल की ओर लाठी-डंडों के साथ जाते देखा। इसके बाद ग्रामीणों ने जंगल में जाकर देखा तो वे पक्षियों को पकड़े थे और उसे बाइक पर लाद रहे थे। इसके बाद ग्रामीणों ने शोर मचा दिया। इससे बाइक सवार उक्त पक्षी को वहीं छोड़कर बाइकों से भाग गए।

हरियाणा का गांव बना मिसाल

फरीदाबाद। जिले में नहर पार स्थित एक छोटा सा गांव बड़ौली। इस गांव की अलग पहचान दी है यहां की मांओं ने। इन्होंने बेटियों का सम्मान बढ़ाया। एक ओर जहां कन्या भ्रूण हत्या, नवजात बच्चियों को लावारिस अवस्था में फेंक देने की घटनाएं बढ़ रही हैं। वहीं दूसरी ओर यह गांव मिसाल बना हुआ है। जहां बेटा और बेटा को एक सम्मान व एक मान दिया जाता है। हरियाणा सरकार की ओर से जल्द ही गांव की पंचायत को सम्मानित भी किया जाएगा।

जिले में एक ओर जहां लड़का-लड़की का लिंगानुपात 1000 की तुलना में 889 है। जबकि जिले के बड़ौली गांव में लिंगानुपात 1000 की तुलना में 1300 है। इसलिए प्रदेश सरकार ने इस गांव को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है। इस गांव में लड़कियों का राज सरकारी स्कूलों में भी कई साल से है। यहां पहली से 10 वीं तक के स्कूल में लड़कियां लड़कों से कहीं ज्यादा हैं। यही नहीं इस स्कूल में 10 वीं में भी अच्छे मार्क्स लड़कियां लेकर आती हैं। पहली से पांचवीं तक 94 बॉयज हैं। जबकि 137 लड़कियां हैं। वहीं छठी से 10 वीं तक भी लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है।

हरे चारे के उत्पादन के लिए मिलेगा अनुदान

गोहाना। अगर आप अपने खेतों में हरे चारे का उत्पादन करना चाहते हैं तो जरूर कृषि विभाग से संपर्क कीजिये। हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना शहर में किसानों को अनुदान में ज्वार और मक्का के बीज उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत किसानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बीज उपलब्ध कराये जायेंगे।

कृषि विभाग के एसडीएओ डा. राजेंद्र प्रसाद मेहरा द्वारा मिली जानकारी के अनुसार किसानों को हरे चारे की बिजाई के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिसके मद्देनजर किसानों को ज्वार व मक्का के बीज अनुदान के तौर पर दिए जा रहे हैं। किसी भी तरह की धांदली न होने के लिए पुरी तरह से एहतियात बरते जा रहे हैं।

U S Agrochem Pvt. Ltd.

Wholesale Supplier

- ❖ अमीना ऐसिड
- ❖ हियूमिक ऐसिड
- ❖ सि-वीड
- ❖ थायोयूरिया
- ❖ सूक्ष्म तत्व मिश्रण तरल एवं दानेदार
- ❖ भूमि सुधारक खाद

व्यापारिक पूछताछ आमंत्रित है

प्लाट नं. बी-81-82, नीलगिरी कॉलोनी, रोड नं. 9 के सामने
वी.के.आई. एरिया, जयपुर-302013 (राज.)
ई-मेल : usagrochem_jaipur@yahoo.com • सम्पर्क : 0141-5140277